A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 28 जनवरी, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 148, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

सऊदी अरब और यूएई के बीच रस्साकशी की असली वजह

नसरीन हातूम

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में सऊदी अरब के सरकारी चैनल 'अल-इख़बारिया' ने अमीराती सरकार पर आरोप लगाया है कि वह सऊदी अरब के ख़िलाफ़ मीडिया मुहिम को हवा दे रही है। 'अल-इख़बारिया' पर आठ दिन पहले जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को नुक़सान पहुंचाने या ख़तरे में डालने वालों के ख़िलाफ़ ज़रूरी क़दम उठाने में नहीं हिचकिचाएगा।

रियाद और अबू धाबी के बीच बढ़ती राजनीतिक खींचतान की पृष्ठभूमि में ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो सतही मतभेदों से आगे बढ़कर इस क्षेत्र के जियो-पॉलिटिक्स से जुड़े विवाद के बुनियादी पहलुओं के इर्द-गिर्द घूमते हैं। इनमें सबसे अहम सवाल यह है कि क्या व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग दोनों खाड़ी पड़ोसियों के बीच एक अघोषित प्रतिद्वंद्विता का मैदान बन गए हैं?

यह सवाल हमें सीधे यमन की तरफ़ ले जाता है, जिसके पास हिंद महासागर, अरब सागर और लाल सागर के साथ 2 हजार किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा है। इसी रास्ते से दुनिया का लगभग 10 से 12 फ़ीसद व्यापार होता है।

'बाब अल-मंदाब' के रणनीतिक जलडमरूमध्य पर भी यमन का क़ब्ज़ा है। यहां से सऊदी तेल टैंकरों सहित व्यापारिक और सैन्य जहाज़ गुजरते हैं। 'रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज़ इंस्टीट्यूट फ़ॉर डिफ़ेंस एंड सिक्योरिटी' से जुड़े यमनी शोधकर्ता बरा शीबान बताते हैं कि यूएई ने क्षेत्रीय जलक्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण मौजूदगी बना ली है। इसके उदाहरण सोमालीलैंड के बरबेरा बंदरगाह में पूंजी निवेश, इरिट्रिया में फ़ौजी अड्डे और यमन में वैसे ठिकाने हैं जो यूएई ने 2025 के अंत में वहां बनाए थे। यूएई की क्षेत्रीय उपस्थिति समुद्री सीमाओं पर मज़बूत पकड़ और अमेरिका के साथ गहरे संबंधों पर आधारित है, जिसका मक़सद यह है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा से जुड़े अमेरिका के बोझ को कम किया जा सके। इस स्थिति ने क्षेत्र में यूएई और सऊदी अरब के बीच एक प्रकार की प्रतिद्वंद्विता को जन्म दिया है। यूएई ने यमन में सशस्त्र बलों और फ़ौजी अड्डों का जाल बिछाकर और सोमालीलैंड के बरबेरा बंदरगाह में निवेश के ज़रिए पोर्ट ऑफ़ अदन में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। इस बंदरगाह पर कंट्रोल यूएई को क्षेत्रीय समुद्री सीमाओं में एक ख़ास बढ़त देता है। हालांकि उनके अनुसार, यह योजना उस वक़्त ख़त्म हो गई जब सऊदी अरब ने यमनी सरकार के समर्थन से यूएई को यमनी बंदरगाहों और कुल मिलाकर लगभग पूरे देश से बाहर कर दिया।

दूसरी तरफ़ यूएई के राजनीतिक विशेषज्ञ अमजद ताहा का मानना है कि इस मामले को कई स्तरों पर परखा जा सकता है। पहला, अदन यमन का प्राकृतिक दक्षिणी प्रवेश द्वार है और इसकी स्थिरता यमन के साथ-साथ पूरे क्षेत्र के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, सोमालीलैंड दूसरी ओर एक लॉजिस्टिक पॉइंट है जो रास्तों में विविधता लाने, व्यापारिक जलमार्गों पर दबाव कम करने और स्थानीय विकास में मदद करता है। अदन और सोमालीलैंड के संबंधों पर वह कहते हैं कि जब दोनों तरफ़ सुविधाएं बेहतर होंगी तो समुद्री डकैती, स्मगलिंग और चरमपंथी समूहों की गतिविधियां कम होंगी। बाब अल-मंदाब आज एक वैश्विक मार्ग है, और इसमें किसी भी रुकावट का असर व्यापार, ऊर्जा, अनाज और यहां तक कि समुद्री बीमा पर पड़ता है। यूएई के क्षेत्रीय विस्तार को इजराइल के साथ सहयोग के तौर पर देखा जा रहा है, ख़ास कर दोनों देशों के बीच संबंधों की बहाली और इसराइल के सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने के बाद। ऐसी कार्रवाई लाल सागर के बारे में सऊदी हितों से टकराती है। यमनी शोधकर्ता बरा शीबान कहते हैं कि सऊदी मानते हैं कि इसराइल और यूएई के बीच एक तरह का गठबंधन है, जिसका मक़सद उन क्षेत्रों में इसराइल की मौजूदगी को मज़बूत करना है जो पारंपरिक रूप से इसराइल के अनुकूल नहीं रहे हैं। इसराइल 2020 में यूएई के साथ हुए 'अब्राहम एकॉर्ड' का इस्तेमाल कर रहा है ताकि दुनिया के इस महत्वपूर्ण हिस्से में अपनी मौजूदगी बढ़ा सके। इस क्षेत्र में विभिन्न शक्तियों के आपसी हितों और शक्ति संतुलन में संभावित बदलावों ने इस स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। यमन में यूएई के बड़े पूंजी निवेश और 'सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल' के समर्थन के बावजूद वह (यूएई) नाकाम रहा और इसका फ़ायदा सऊदी अरब को हुआ। हालांकि यूएई अब भी इरिट्रिया में सैन्य तैनाती और सूडान में 'रैपिड सपोर्ट फ़ोर्सेज़' के समर्थन से अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। भविष्य में अमीराती हस्तक्षेप इस बात पर निर्भर करेगा कि वह सऊदी अरब के साथ जलडमरूमध्यों और क्षेत्रीय जलक्षेत्र पर प्रतिद्वंद्विता के ख़तरों को किस रूप में देखता है।

अमजद ताहा का मानना है कि हालांकि बंदरगाहों और निवेश जैसे क्षेत्रों में आर्थिक 'ओवरलैप' मौजूद है लेकिन लाल सागर में सऊदी और अमीराती हित एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हैं। दोनों देशों को एक जैसे ख़तरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा की समस्या, हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग, आतंकवादी समूह, हूती विद्रोहियों की धमकियां और व्यापारिक रुकावटें शामिल हैं। लाल सागर में यूएई की योजना टकराव की नहीं बल्कि स्थिरता की योजना है।,यूएई एक वैश्विक व्यापारिक देश के रूप में अपने स्वाभाविक अधिकार का उपयोग कर रहा है। अबू धाबी समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने की कोशिश कर रहा है जिसमें समुद्री डकैती और तस्करी के ख़िलाफ़ कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की रक्षा शामिल है।'

इसी दौरान सऊदी अरब का सोमालिया और मिस्र के साथ सैन्य गठबंधन ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिमी अख़बारों ने रिपोर्ट दी कि सऊदी अरब अफ़्रीका में यूएई के प्रभाव को कम करने के लिए सोमालिया और मिस्र के साथ एक नए सैन्य गठबंधन की कोशिश कर रहा है। सोमालिया ने आरोप लगाया कि यूएई ने उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। सोमालिया के लिए संप्रभुता का मुद्दा अधिक संवेदनशील हो गया है, क्योंकि वह सोमालीलैंड के साथ यूएई और इजराइल के संबंधों को अपनी सुरक्षा के लिए ख़तरा मानता है। सऊदी अरब और मिस्र ने सोमालिया की एकता का समर्थन किया है और इजराइल द्वारा सोमालीलैंड को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने की निंदा की है। इस तरह सऊदी अरब की तरफ़ से सोमालिया और मिस्र के साथ नए सैन्य गठबंधन की कोशिश को यूएई और इजराइल की क्षेत्रीय उपस्थिति बढ़ाने के प्रयासों का मुक़ाबला करने के तौर पर देखा जा सकता है। यही वजह है कि क्षेत्र के महत्वपूर्ण जलमार्गों और बंदरगाहों के आसपास रणनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जो सऊदी-अमीराती प्रतिद्वंद्विता और नए खिलाड़ियों के असर की वजह से अप्रत्याशित बदलावों का शिकार हो सकता है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

जब जाओ तब
छोड़ जाना...
थोड़ा प्यार
थोड़ी कोमलता
थोड़ा बचपना

जब जाओ तब
छोड़ जाना...
थोड़ा सच
थोड़ा ईमान
थोड़ी आग

जब जाओ तब
छोड़ जाना...
थोड़े स्वप्न
थोड़ी मीठी नींद
थोड़ा अल्हड़पन

जब जाओ तब
छोड़ जाना...
थोड़ा गुस्सा
थोड़ा पागलपन
थोड़ा अपनापन

तुम जाओ
जाना तो है–ही
जाओ तो कह जाना
तुम बने रहना
थोड़ा आदमी।

–दुर्गाप्रसाद झाला

शंकराचार्य मामले पर इस्तीफा देने वाले बरेली मजिस्ट्रेट सस्पेंड

● डीएम से मिलने नहीं दिया तो दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे

बरेली (एजेंसी)। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान में इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को शासन ने सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि, अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। माना जा रहा कि जांच पूरी होने के बाद ही सरकार इस्तीफा स्वीकार करेगी। फिलहाल, अग्निहोत्री को शामली अटैच कर दिया गया। बरेली कमिश्नर को मामले की जांच सौंपी गई है। मजिस्ट्रेट से सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई है। वह मंगलवार सुबह 11 बजे डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। नाराज होकर वे कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा- इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, सरकार से मोहभंग हो गया। अब मुझे आगे क्या करना है ये समाज तय करेगा। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।

भारत-यूरोपीय यूनियन में 18 साल बाद ट्रेड डील

● इम्पोर्टेड लग्जरी कारों पर टैरिफ 110 से घटकर 10 फीसदी होगा

प्रीमियम शराब पर 150 फीसदी की जगह 20 फीसदी टैक्स लगेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) हो गया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने 16वें भारत-ईयू समिट के दौरान इसका ऐलान किया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। इस डील के बाद भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110 से घटाकर 10 फीसदी कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है।

● **ट्रेड डील से 43 हजार करोड़ के टैरिफ कम होंगे–** उर्सुला वान डेर लेयेन ने कहा कि यह समझौता दुनिया को साफ संदेश देता है कि ग्लोबल चुनौतियों का सबसे अच्छा जवाब सहयोग है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत और यूरोप की सप्लाई चेन आपस में जुड़ेंगी और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग ताकत मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि इससे हर साल करीब 4 अरब यूरो (43.5 हजार करोड़ रुपए) के टैरिफ कम होंगे।

● **यूरोपीय संघ के नेता एंटोनियो कोस्टा हुए गद्गद–** वहीं, यूरोपीय संघ के नेता एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ रणनीतिक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में एक साथ खड़े हैं... और हम अपनी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं, ताकि एक लचीली वैश्विक व्यवस्था को आकार दिया जा सके जो शांति और स्थिरता को सक्षम बनाए। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।

देशभर में यूजीसी के नए नियमों का विरोध शुरू

● यूजीसी के खिलाफ बढ़ता जा रहा सवर्ण समाज का गुस्सा ● दिल्ली हेडक्वार्टर की बढ़ाई गई सुरक्षा, यूपी में चूड़ियां भेजीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में यूजी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने जगह-जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडेय ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है।

किसान कल्याण वर्ष में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का है संकल्प : मुख्यमंत्री

बाबई-मोहासा औद्योगिक क्षेत्र के विकास से स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में देश के साथ बदल रहा मध्यप्रदेश भी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को हर क्षेत्र में लगातार बड़ी सौगातें मिल रही हैं। पिछले 11 वर्षों के कालखंड में संपूर्ण देश के साथ हमारा प्रदेश भी बदल रहा है। राज्य सरकार ने वर्ष-2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। पूरे साल में अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुंदेलखंड से केन-बेतवा नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र के कई जिलों के किसानों के खेतों में फसलें लहलहाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्रगति में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में नर्मदापुरम जिले में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए

215 करोड़ 47 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। इससे सोहागपुर और पिपरिया क्षेत्र के किसानों एवं स्थानीय जनजातीय भाई-बहनों को अनुपम सौगात मिली है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री निवास में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह ने क्षेत्रवासियों को मिली सौगातों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार माना। सोहागपुर से आए पार्टी पदाधिकारी, स्थानीयजन एवं विस्थापित जनजातीय परिवारों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आत्मीय अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का वार्षिक बजट अब 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है।

सोहागपुर विधानसभा के 63 गांवों को मिलेगा पर्याप्त जल

विधायक विजयपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश का कोना-कोना सिंचाई सुविधा से लैस हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता से किया अपना वादा निभाया और आज कैबिनेट ने क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए लगभग 226 करोड़ रुपए लागत की दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि तवा परियोजना (दायीं तट नहर) की बागरा शाखा नहर होज सिंचाई परियोजना से बाबई एवं सोहागपुर तहसील के 33 गांवों की 4200 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।

कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति का दिखा जोरदार प्रदर्शन

ब्रह्मोस, सूर्यास्त्र से लेकर अर्जुन टैंक की सुनाई दी गड़गड़ाहट

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने सोमवार को 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई मिसाइलें, युद्धक विमान, नवगठित इकाइयां और घातक हथियार प्रणाली शामिल थीं।

यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की थीम 'वंदे मातरम के 150 वर्ष' है। समारोह शुरू होने से पहले, राष्ट्रपति मुर्मू पारंपरिक बग्गी में बैठकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई अन्य केंद्रीय मंत्री, देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी, विदेशी राजनयिक और वरिष्ठ अधिकारी कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का गवाह बने। परेड में प्रदर्शित प्रमुख हथियार प्रणालियों में ब्रह्मोस और आकाश हथियार प्रणाली, रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन और स्वदेशी रूप से निर्मित सैन्य प्लेटफार्मों और हार्डवेयर की एक श्रृंखला शामिल थी। करीब 100 सांस्कृतिक कलाकारों की परेड की शुरुआत हुई, जिसका विषय विविधता में एकता है। इसके जरिए देश की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हुए संगीत वाद्ययंत्रों की एक भव्य प्रस्तुति दी गई। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू की ओर से सलामी लेने के साथ परेड की शुरुआत हुई। परेड का नेतृत्व जनरल भवनीश ने किया।

ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी

मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ओर से तैनात प्रमुख हथियार प्रणालियों की प्रतिकृतियों को प्रदर्शित करने वाली त्रि-सेवा झांकी एक प्रमुख आकर्षण रही। ब्रह्मोस और एस-400 मिसाइलों जैसी हथियार प्रणालियों के उपयोग के साथ ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को दर्शाने वाले, एक कांच के आवरण वाले एकीकृत परिचालन केंद्र ने कर्तव्य पथ पर खूब तालियां बटोरी। पहली बार, परेड में भारतीय सेना के चरणबद्ध बैटल ऐरे फॉर्मेट का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक हवाई यूनिट शामिल थी। इसमें एक उच्च गतिशीलता टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद प्रकाश विशेषज्ञ वाहन शामिल था। हवाई सहायता प्रदान करने के लिए स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसका सशस्त्र संस्करण, रुद्र, प्रहार फॉर्मेशन में, युद्ध के मैदान को आकार देने का प्रदर्शन कर रहा था।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 28 जनवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

बजट सत्र से पहले सरकार की ऑल पार्टी मीटिंग

● सर्वदलीय बैठक में 35+पार्टियों के सांसद शामिल ● 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडों पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में 35+ पार्टियों के सांसद शामिल हुए। इस दौरान बजट सत्र को सकारात्मक और सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा हुई। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। इस दिन रविवार है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के विधायी एजेंडा

शेयर नहीं करने के आरोप पर कहा कि साल के पहले सेशन में राष्ट्रपति के भाषण के बाद सरकारी कामकाज शेयर किया जाता है। हमें लोगों के मुद्दे उठाने के लिए चुना गया है, हमें बोलने की आजादी है। लेकिन सुनना भी हमारी जिम्मेदारी है। लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं, जिनमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025 और संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 शामिल हैं। इन विधेयकों की वर्तमान में संसदीय स्थायी या प्रवर समितियां जांच कर रही हैं। 2026-27 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा। वित्त मंत्री 7.4 फीसदी विकास दर और अनिश्चित जियो पॉलिटिक्स के बीच 1 फरवरी को बजट पेश होगा।

तेलंगाना के गांव में 200 और आवारा कुत्तों की हत्या

● पंचायत सचिव पर जहरीले इंजेक्शन से मरवाने का आरोप

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के हनमकोंडा जिले के पथीपाका गांव में 200 आवारा कुत्तों की हत्या कर दी गई। एनिमल वेल्फेयर ऐक्टिविस्ट के दावे के मुताबिक, गांव के सरपंच ने दिसंबर में हुए पंचायत चुनाव में लोगों से कुत्तों से छुटकारा दिलाने का वादा किया था। करीब एक महीने पहले, वादा पूरा करने के लिए कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन दे दिया गया। फिर कुत्तों के शवों को गांव के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। दावा है कि

यह सब ग्राम पंचायत सचिव की निगरानी में हुआ। इससे पहले, हनमकोंडा जिले के श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में भी 6 जनवरी से 9 जनवरी के बीच लगभग 300 आवारा कुत्तों की हत्या का मामला सामने आया था। तेलंगाना के कुल तीन जिलों में दिसंबर 2025 से अब तक 1100 कुत्तों की हत्या हो चुकी है। 22 जनवरी को जगतियाल जिले के पेगाडापल्ली गांव में करीब 300 कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देने हत्या का मामला सामने आया था। इस मामले में सरपंच और पंचायत सचिव के खिलाफ बीएनएस और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। इससे पहले 100 कुत्तों को मारे जाने की खबर थी।

नीट छात्रा को 8 साल बाद रेलवे से मिल गया इंसाफ

अब 9.10 लाख रुपए देगा रेलवे, लड़ी लंबी लड़ाई

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक नीट स्टूडेंट को 8 साल बाद इंसाफ मिला है। रेलवे को मुआवजे के तौर पर अब छात्रा को 9 लाख 10 हजार रुपये देने होंगे। इसमें देरी से भुगतान के लिए 12 प्रतिशत ब्याज भी जोड़ा गया है। इस पर कुछ लोगों को शायद विश्वास भी न हो लेकिन यह सच है कि रेलवे को यह मुआवजा लेट-लतीफी की वजह से चुकाना पड़ रहा है। कई साल के धैर्य, दृढ़ निश्चय और सही चीज के लिए लड़ने की सोच से छात्रा ने जीत हासिल की। यह मामला उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नजीर है जो जेईई-नीट, यूपीएससी, एसएससी या बैंक समेत भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा के वजह से काफी ट्रैवल कर रहे हैं। दरअसल, 2018 यानी करीब 8 साल पहले

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले की रहने वाली एक छात्रा समृद्धि घर से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने घर से निकली थी। उसे लखनऊ के जय नारायण पीजी कॉलेज एग्जाम सेंटर पर पहुंचना था। छात्रा ने बस्ती से इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन का टिकट खरीदा। ट्रेन को सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंचना था, लेकिन वह ढाई घंटे देरी से पहुंची, जबकि छात्रा रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से ठीक समय पर ट्रेन में चढ़ी थी। उसे 12.30 बजे तक एग्जाम सेंटर पर पहुंचना था। वह समय पर एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाई और उसका एग्जाम छूट गया। उसका साल बर्बाद हो गया था। ट्रेन की लेट-लतीफी की वजह से छात्रा ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया।

गंगोत्री में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन को लेकर विरोध

● अरशद मदनी और इमरान मसूद ने फैसले पर उठाए सवाल

सहारनपुर (एजेंसी)। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में भी इस दिशा में कदम उठाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस पूरे मामले पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। अरशद मदनी ने कहा,उन्हें लगता है कि देश उनका

है, और वे जनता को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन समय बदल गया है। यह अच्छी बात है कि लोग प्यार और भाईचारे से रहें और जमीयत उलेमा-ए-हिंद यही सिखाता है। यह सिर्फ केदारनाथ में नहीं है। असम में पूरी कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है और लाखों मुसलमानों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मुद्दे पर विरोध किया है।

चीन-पाकिस्तान सीमाओं की और ज्यादा बढ़ेगी निगरानी

सेना का खास प्लान, बनाए जा रहे एयर कमांड सेंटर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ कम-ऊंचाई वाले वायु क्षेत्र की निगरानी करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। सेना 35 किलोमीटर की भूमि दूरी और 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाली सभी वस्तुओं, खासकर दुश्मन ड्रोनों की निगरानी करने की क्षमता विकसित कर रही है। यह पहल मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान ने तुर्की और चीनी सशस्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल कर भारतीय सेना और वायुसेना के ठिकानों पर हमले किए थे। सीमाओं पर एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जो न केवल ड्रोन गतिविधियों की निगरानी करेंगे, बल्कि दुश्मन ड्रोनों को लॉन्च और न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम होंगे। वर्तमान में सेना 97 फीसदी ड्रोन और एंटी-ड्रोन गतिविधियों को इसी 35×3 किमी दायरे में संभाल रही है। इस प्लान के तहत पश्चिमी थिएटर में 10,000 ड्रोनों के संचालन की क्षमता विकसित की जा रही है, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3,488 किमी क्षेत्र में 20,000 से अधिक ड्रोनों की तैनाती की योजना है। सेना ने दो रॉकेट फोर्स यूनिट, दो रुद्र ब्रिगेड और 21 भैरव बटालियन तैनात की हैं। भारतीय तोपखाने की रेंज 150 किमी से बढ़ाकर 1,000 किमी तक कर दी गई है। क्षेत्रीय कोर कमांडर भारतीय वायुसेना के कमांडरों के साथ समन्वय कर रहे हैं।

एमपी में 7 हजार बैंक शाखाओं में कामकाज ठप

40 हजार बैंककर्मी हड़ताल पर, 5-डे वीक की मांग, भोपाल में वित्त मंत्री के खिलाफ नारेबाजी

भोपाल (नप्र)। बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग यानी, पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर मंगलवार को एमपी के करीब 40 हजार बैंककर्मी हड़ताल पर हैं। इससे बैंकों की 7 हजार से ज्यादा ब्रांच में ताले लटके दिखे। एक ही दिन में लाखों-करोड़ रुपए के कारोबार पर असर पड़ेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर यह हड़ताल की जा रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर-ग्वालियर समेत प्रदेशभर की बैंकों में ताले लटके दिखाई दिए। इससे चेक क्लियर, लेन-देन जैसे कामों पर असर पड़ेगा, वहीं एटीएम में रुपयों की कमी भी हो सकती है।

भोपाल में सरकारी प्रेस के सामने सभा

भोपाल के एमपी नगर में सरकारी प्रेस के पास पंजाब नेशनल बैंक शाखा के सामने रैली निकालने के बाद सभा आयोजित की गई है। यहां बड़ी संख्या में बैंककर्मी मौजूद हैं।

डिजिटल सेवा पर असर नहीं

बैंक की हड़ताल का असर डिजिटल लेनदेन पर नहीं पड़ा। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं 24×7 चालू काम करती रही।

फोटो : प्रवीण वाजपेई

उज्जैन के कॉसमॉस मॉल पर जुटे बैंककर्मी

उज्जैन की 290 बैंकों के 4 हजार से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड यूनियन ऑफ बैंक फोरम के संयोजक विपिन सतोरिया ने बताया कि बैंक कर्मचारी यूनियन ने देश भर के बैंक कर्मचारियों को इस हड़ताल में शामिल होने को कहा था। मंगलवार सुबह 11 बजे कॉसमॉस मॉल के सामने केनरा बैंक की ब्रांच पर बड़ी संख्या में बैंक कर्मी एकत्रित हुए और उन्होंने नारेबाजी करते हुए अपनी मांग रखी।

सतोरिया ने कहा कि हमारी मुख्य मांग हफ्ते में पांच दिन काम करने का नियम तुरंत लागू किये जाने की है। इस हड़ताल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक जैसे नाम शामिल हैं। 8 मार्च 2024 को सरकार और बैंक यूनियन के बीच समझौता हुआ था कि पांच दिन की वर्किंग दी जाएगी। 690 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी फैसला इस पर नहीं हो पाया है। इस कारण देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर है।

गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा यह कलेक्टर ही तय करेंगे

● सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर मामले में साफ किया अपना रुख

वीआईपी दर्शन याचिका की खारिज, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार

उज्जैन (एजेंसी)। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नेताओं और वीआईपी को प्रवेश देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे पहले इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही इंदौर हाईकोर्ट का फैसला महाकाल मंदिर समिति पर लागू रहेगा, जिसमें उज्जैन कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे तय करें कि कौन वीआईपी है और कौन नहीं। दरअसल, महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद इंदौर के अधिवक्ता चर्चित शास्त्री और दर्पण अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि देशभर से लाखों श्रद्धालु महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं,जबकि नेता और प्रभावशाली लोग गर्भगृह पहुंचते हैं।

पहले कनाडा जा रहे डोभाल, फिर भारत आएंगे कार्नी

नई दिल्ली (एजेंसी)। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मार्च के पहले हफ्ते में भारत आ सकते हैं। उससे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के कनाडा जाने की चर्चा है। कनाडा में सत्ता परिवर्तन के बाद जबसे कार्नी ने कमान संभाली है, भारत और कनाडा के बीच आपसी संबंधों में काफी सुधार हुए हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक और अन्य मसलों पर तो चर्चा हो ही रही है और संबंधों को व्यापक बनाने पर काम चल रहा है, लेकिन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी कनाडा से संबंध खास मायने रखते हैं। ऐसे में यह दोनों ही यात्राएं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल फरवरी में कनाडा की यात्रा पर जा सकते हैं।

डोभाल और ड्रोइन में पहले भी हुई बात

मार्क कार्नी के कार्यकाल से पहले दोनों देशों के बीच संबंधों में इतनी कड़वाहट आ गई थी कि उच्चायोग भी बंद पड़ गए थे,जो 2025 के अगस्त से फिर से काम कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में कनाडा की सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली ड्रोइन दिल्ली आई थीं और उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से सुरक्षा संबंधों को लेकर विस्तृत चर्चा की थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह चर्चा मुख्य तौर पर उस द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाने पर केंद्रित रही, जो 2023 में बिगड़ गई थी।

ड्यूटी के दौरान कुर्सी पर हुए बेहोश, तहसील कार्यालय के सेक्शन राइटर थे

सतना कलेक्ट्रेट में कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत

सतना (नप्र)। सतना जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को रघुराजनगर तहसील कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी संजय मिश्रा का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। वे सेक्शन राइटर के पद पर कार्यरत थे और उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे संजय मिश्रा तहसील कार्यालय में अपने नियमित कार्य में व्यस्त थे। इसी दौरान उन्हें अचानक चक्कर आया और वे कुर्सी पर बैठे-बैठे ही बेहोश होकर गिर पड़े। सहकर्मियों ने तत्काल उन्हें संभाला और निजी वाहन से अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की।

सतना कलेक्ट्रेट में शोक की लहर, सहकर्मियों ने दी श्रद्धांजलि- हालांकि, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। बताया गया है कि सेक्शन राइटर संजय मिश्रा 59 वर्ष के थे। 3 साल नौकरी

के बचे थे। संजय मिश्रा पहले से ही हार्ट पेशेंट थे। उनकी एंजियोप्लास्टी पहले भी हो चुकी थी।

उनके निधन की खबर मिलते ही परिजन तत्काल अस्पताल पहुंचे, जहां शोक का माहौल बन गया। सहकर्मियों ने संजय मिश्रा को एक कर्मठ, सरल और जिम्मेदार कर्मचारी बताया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अधिकारियों ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

प्रदेश में 4000 मेगावाट की थर्मल पॉवर यूनिट लगेंगी

सीएम मोहन बोले- जैसे शरीर के लिए प्राण जरूरी वैसे ही राज्य की प्रगति के लिए बिजली

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बिजली का महत्व आज के दौर में ऐसा है जैसे शरीर में प्राण का महत्व है। जिस तरह से जीवन की सभी गतिविधियों के संचालन के लिए शरीर में प्राण आवश्यक है, वैसे ही किसी भी राज्य की प्रगति और उन्नति के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्धता आवश्यक है। प्रदेश में 60 हजार करोड़ रुपए की लागत से 4 हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन के लिए हुए समझौते प्रदेश के स्थाई विकास का आधार बनेंगे।

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि इससे प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ

बिजली की मांग की सौ फीसदी आपूर्ति संभव होगी। डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट (डीबीएफओओ) मॉडल पर स्थापित होने वाले इन नए विद्युत संयंत्रों से लगभग 8000 लोगों को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर हुए

सीएम यादव ने ये बातें आज सीएम निवास के समत्व भवन में कहीं। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और ऊर्जा विभाग के अफसरों की मौजूदगी में एमओयू साइन किए गए। अनूपपुर जिले में इन परियोजनाओं की स्थापना एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से की जाएगी। नई ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए डीबीएफओओ आधार पर प्रतिस्पर्धात्मक टेंडर प्रोसेस कराई गई है। इस प्रक्रिया में कुल 3200 मेगावाट क्षमता के लिए तीन सफल डेवलपर्स का चयन किया गया है। साथ ही शासन की स्वीकृति के अनुसार अतिरिक्त 800 मेगावाट क्षमता का आवंटन भी किया गया है। इसमें मेसर्स हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 800 मेगावाट, मेसर्स टोरेंट पावर लिमिटेड को 1600 मेगावाट तथा मेसर्स अदानी पावर लिमिटेड को 800 मेगावाट क्षमता आवंटित की गई है। ग्रीनफील्ड विकल्प के अंतर्गत अतिरिक्त 800 मेगावाट क्षमता का आवंटन किया गया है। सभी परियोजनाओं के लिए विद्युत आपूर्ति अनुबंध संबंधित विकासकर्ताओं द्वारा गठित स्पेशल पर्पस व्हीकल के साथ किए गए हैं।

पीएससी एवं कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जा रही भर्ती प्रक्रिया की नियमित करें समीक्षा : शुक्ल

चिकित्सकीय अधोसंरचना विकास कार्यों और उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा कर दिए निर्देश

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की समीक्षा की। बैठक में चिकित्सकीय सहायक चिकित्सकीय मैनपावर भर्ती से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मेडिकल ऑफिसर एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से सीधे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा की पीएससी एवं कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जा रही भर्ती प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जाये। समस्त औपचारिकताओं की प्राथमिकता से पूर्ति की जाये। बैठक में एएनएम के शेष रिक्त पदों पर प्राथमिकता से पूर्ति के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए वर्तमान में उपलब्ध मॉडलों की विस्तृत समीक्षा कर शीघ्र आवश्यक भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की समय पर पदस्थापना अनिवार्य है। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी तथा मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा। बताया गया कि अग्रेषित 1377 विशेषज्ञ भर्ती प्रक्रिया में 500 विशेषज्ञों की सूची प्राप्त हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में नर्सिंग शिक्षकों की भर्ती में आ रही व्यवहारिक एवं प्रक्रियात्मक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भर्ती से संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विभागीय जानकारी और स्पष्टीकरण शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रेषित करने के निर्देश दिए ताकि मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके

और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मेडिकल कॉलेज बुधनी, मंडला, सागर एवं रीवा में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पुनरीक्षित स्वीकृति से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं समय-सीमा में पूर्ण की जाएं, जिससे विकास कार्यों में किसी प्रकार का विलंब न हो और शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार निर्धारित समय में किया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा, ग्वालियर, जबलपुर सहित चिन्हित मेडिकल कॉलेजों में उन्नत कैंसर उपचार सुविधाओं के विस्तार के लिए अधोसंरचना विकास एवं आवश्यक उपकरणों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण कैंसर उपचार उपलब्ध कराना है, जिससे मरीजों को अन्यत्र रेफर करने की आवश्यकता कम हो।

सीएम केयर्स योजना के क्रियान्वयन के लिए की जा रही गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर मंत्रि-परिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन कार्यों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए गए कि बजट की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय अधोसंरचना विकास कार्यों में विभागीय उदासीनता के कारण किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए तथा सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज बुधनी, छतरपुर और दमोह में आगामी-सत्र से संचालन प्रस्तावित है, इसके लिए अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ति चरण में हैं। संचालन के लिए फर्नीचर, उपकरण और आवश्यक शैक्षणिक और सहायक मैनपावर भर्ती का कार्य भी समय से पूर्ण करें, जिससे एनएमसी अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। बैठक में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री धनराजू एस, एमडी एमपीपीएचएससीएल श्री मयंक अग्रवाल, संचालक स्वास्थ्य श्री दिनेश श्रीवास्तव, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुणा कुमार, संचालक श्रीमती मल्लिका निगम नागर, संचालक वित्त (एनएचएम) श्री वीरभद्र शर्मा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सड़क दुर्घटना में घायल बालक को काफिला रुकवाकर तत्काल उपलब्ध कराई चिकित्सकीय सहायता

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सागर प्रवास से वापसी के दौरान विदिशा-भोपाल मार्ग पर सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर तत्काल अपना काफिला रुकवाकर मौके पर अचेत अवस्था में घायल बालक को तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए फॉलो वाहन से बालक को तुरंत निकटतम अस्पताल पहुंचाया। साथ ही संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सकीय स्टाफ को आवश्यक उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बालक अंकित कुमार यादव को समय पर निकटवर्ती अस्पताल पहुंचाकर आवश्यक चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। बालक का स्वास्थ्य स्थिर है। घटना के संबंध में स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

उपभोक्ताओं को मिले गुणवत्तापूर्ण बिजली : ऊर्जा मंत्री तोमर

विद्युत सप्लाई में ट्रिपिंग के कारण न हो दिक्कत गलत बिजली बिल प्राथमिकता से सुधारें

भोपाल (नप्र)। किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और उद्योगों को सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ट्रिपिंग की समस्या कम से कम होनी चाहिए। समाधान योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात मंगलवार को विभागीय योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान कही।

मंत्री श्री तोमर ने मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं से बात कर विद्युत आपूर्ति और समाधान योजना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। मेंटेनेंस में कोताही नहीं बरतें। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि समाधान योजना में कितना बिजली बिल बकाया है, कितना वसूली योग्य है और कितना वसूली योग्य नहीं है, इसकी पूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि बड़े डिफॉल्टरों के विरूद्ध पहले कार्रवाई करें।

मंत्री श्री तोमर ने जोर देकर कहा कि उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली दें और साथ ही अच्छी वसूली भी करें। गलत बिजली बिलों को सुधारने की कार्यवाही प्राथमिकता से करें। कार्यों पर

लापरवाही पर नोटिस जारी करें।

समाधान योजना में अभी तक जमा हुए 745 करोड़ 92 लाख रूपये- समाधान योजना में अभी तक 745 करोड़ 92 लाख रूपये उपभोक्ताओं द्वारा जमा कराएं जा चुके है। इन उपभोक्ताओं के 301 करोड़ 40 लाख रूपये के सरचार्ज माफ किये गए है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अंतर्गत 150 करोड़ 22 लाख, मध्य क्षेत्र में 469 करोड़ 47 लाख और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में 126 करोड़ 23 लाख रूपये जमा हुए हैं।

बैठक में सचिव ऊर्जा श्री विशेष गढ़पाले, एमडी पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री अनूप सिंह, एमडी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री ऋषि गर्ग एवं तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के चीफ इंजीनियर और एसई उपस्थित थे।

सिंघार बोले- एमपी कांग्रेस की दिल्ली से हो रही मॉनिटरिंग

जितनी जल्दी संगठन खड़ा होगा, चुनावी तैयारी उतनी प्रभावी होगी

भोपाल (नप्र)। नई दिल्ली में 28 जनवरी को कांग्रेस की अहम बैठक है। इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। इसके पहले भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर पूरी तरह अलर्ट है और प्रदेश के कामकाज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

उतनी ही प्रभावी होगी चुनाव की तैयारी- उमंग सिंघार ने कहा कि संगठन जितनी जल्दी पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा, चुनाव की तैयारी उतनी ही प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस में सभी नेता और कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।

यूजीसी के नए नियमों को लेकर सरकार पर निशाना- यूजीसी के नए नियमों को लेकर जारी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि देश में कई वर्ग हैं और सरकार को कानून बनाते समय सभी वर्गों की राय को महत्व देना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार चौपाल और संवाद की बात तो करती है, लेकिन जब कानून बनाने का समय आता है, तब सभी पक्षों से राय क्यों नहीं ली जाती। उन्होंने कहा कि नीति बनाते वक्त संवाद सिर्फ औपचारिक नहीं, वास्तविक होना चाहिए,।

लाइव विधानसभा कार्यवाही का मुद्दा उठा- आगामी बजट सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर विधानसभा की कार्यवाही को लाइव दिखाने की मांग उठाई है।

उमंग सिंघार ने कहा-सरकार विधानसभा की कार्यवाही लाइव दिखाने से क्यों डरती है? देश के कई छोटे राज्य कार्यवाही का सीधा प्रसारण करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं होता? कांग्रेस विधायक सदन के भीतर जनता के मुद्दे मजबूती से उठाते हैं।अगर विधानसभा की कार्रवाई लाइव दिखाई जाए, तो हमें बाहर विरोध-प्रदर्शन करने की जरूरत ही न पड़े।

इलेक्ट्रॉनिक हैंड से 23 साल बाद फिर चला सकेंगे वाहन

अब तक 328 लोगों को मिले नए हाथ, भोपाल में कैंप का आखिरी दिन था

भोपाल (नप्र)। साल 2003 में सिरोंज में अपने खेत में काम करते समय महेंद्र सिंह करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में उनके दोनों हाथ जल गए। अब साल 2026 में करीब 23 साल बाद उन्हें नए हाथ मिलने जा रहे हैं। महेंद्र का कहना है कि यह बेहद भावुक पल है। 23 साल बाद ऐसा होगा कि वे वाहन तक चला सकेंगे। दोनों हाथ ना होने से वे अपने दैनिक कार्यों के लिए भी परिवार पर आश्रित थे। अब यह हाथ लगने से अपने काम खुद कर सकेंगे।

अकेले महेंद्र ही नहीं बल्कि मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष कैंप आयोजित कर अब तक 328 लोगों को इलेक्ट्रॉनिक हैंड लगाए जा चुके हैं। हथाईखेड़ा सिविल अस्पताल में इस विशेष कैंप के जरिए नए आर्टिफिशियल हाथ दिए जाएंगा। अब तक अकेले भोपाल में 142 लोग इस कृत्रिम हाथ के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हर मरीज की जरूरत के अनुसार अलग-अलग साइज के इलेक्ट्रॉनिक हैंड तैयार किए गए।

सीएमएचओ बोले- अब लोग खुद से पानी पी सकेंगे- सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कृत्रिम हाथ NHM (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के जरिए उन लोगों को लगाए जा रहें हैं, जिनके कोहनी के नीचे से हाथ नहीं हैं। इसके जरिए वे रोजमर्रा के कार्य कर सकेंगे। दूसरों पर उनकी निर्भरता भी कम होगी। इस हाथ की मदद से व्यक्ति ग्लास पकड़ सकता है, गाड़ी चला सकता है और यह दो साल की बैटरी की वारंटी के साथ दिया जा रहा है। दो दिन में इसे एक बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। अभी जो लोग पानी पीने तक के लिए दूसरों की मदद मांगते थे, वे इस तरह के सभी काम खुद कर सकेंगे।

करंट ने छीने सबसे ज्यादा हाथ- भोपाल में जो पीड़ित इलेक्ट्रॉनिक हैंड लगवाने आए उसमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं, जिनका करंट ने हाथ छीन लिया। इसके बाद दूसरे नंबर पर एक्सीडेंट और हादसे में लोगों ने हाथ गवाएं। वहीं, तीसरे नंबर पर जन्मजात हाथ ना होने की बात सामने आई।

गणतंत्र दिवस पर 'लखपति दीदी' थीम पर जिलों में हुआ झांकी प्रदर्शन

उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया ड्रोन दीदी रूपाली मोदी को सम्मानित

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 26 जनवरी 2026 को पहली बार 'लखपति दीदी' थीम पर मिशन अंतर्गत विभिन्न जिलों में झांकी प्रदर्शित की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलों में आयोजित समारोहों में प्रदर्शित की गई इन झांकियों में अधिकांश जिलों को पुरस्कार मिले हैं।

उज्जैन जिले मे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तराना विकासखण्ड के डबलाहरदू ग्राम की ड्रोन दीदी श्रीमती रूपाली मोदी को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए मंच से सम्मानित किया।

इसी क्रम में जिलों द्वारा झांकी प्रदर्शन किया गया- 38 जिलों द्वारा इसी विषय पर झांकी निकाली गई। इसमें से 10 जिलों ने प्रथम स्थान, 7 जिलों ने द्वितीय एवं

7 जिलों ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है।

प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने बाले जिलों में खरगोन, सिंगरोली, पन्ना, ग्वालियर, कटनी, नीमच, सतना, मैहर, शहडोल एवं बालाघाट शामिल हैं। द्वितीय पुरस्कार रायसेन, उज्जैन, मुरैना, लीराजपुर, झाबुआ, देवास एवं रतलाम जिले ने हासिल किया है। तृतीय पुरस्कार सीहोर, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, छतरपुर, इंदौर एवं हरदा जिले ने प्राप्त किया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी आजीविका मिशन श्रीमती हर्षिका सिंह ने जिलों में प्रदर्शित होने बाली झांकियों में मिशन अंतर्गत लखपति दीदी थीम को शामिल करते हुए झांकी प्रदर्शन के लिए निर्देशित किया था।

प्रदेश में 45 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में होती है फूलों की खेती

पुष्प उत्पादन को दिया जायेगा व्यवसायिक स्वरूप : उद्यानिकी मंत्री कुशवाह

भोपाल (नप्र)। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि प्रदेश में पुष्प उत्पादन को व्यावसायिक स्वरूप दिया जाएगा। पुष्पों के उत्पादन के प्रति किसानों को आकर्षित करने के लिये 30 जनवरी को राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा गुलाब उद्यान में किया जायेगा। प्रदर्शनी में पुष्प उत्पादक कृषक, पुष्प विशेषज्ञ, नर्सरी व्यवसाय से जुड़े उद्यमी, पुष्प उत्पादक संस्थाओं के प्रतिनिधि, कृषि विश्वविद्यालयों के छात्र तथा पुष्प प्रेमी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पुष्प उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश के लगभग 45 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती की जा रही है जिसमें 5 लाख मी.टन फूलों का उत्पादन प्रतिवर्ष हो रहा है। प्रदेश में लगभग 40 हजार किसान फूलों की खेती से जुड़े हुए हैं।

मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि राज्य शासन का लक्ष्य फूलों के उत्पादन के व्यावसायिक स्वरूप प्रदान करते हुए किसानों की आय को दोगुना करना है। मध्यप्रदेश को पुष्प उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। प्रदेश के ऐसे धार्मिक स्थान और शहर जिनमें फूलों की अधिक मांग रहती है उनके आस-पास पुष्प उत्पादन क्लस्टर विकसित करने कार्य योजना बनायी गई है। इसी कडी में उद्यानिकी विभाग द्वारा 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले को बडे अवसर के रूप में देख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन के यादव पहल पर उज्जैन के आस पास लगभग 100 एकड़ में फूल उत्पादन का विशेष क्लस्टर विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है।

मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि प्रदेश के गुना जैसे छोटे जिले के किसानों द्वारा गुलाब उत्पादन में देश और विदेश में नई पहचान बनाई है। गुना का गुलाब दिल्ली, मुम्बई, बैंगलौर सहित विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा फूलों के उत्पादन को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना से भी जोडा गया है। अनेक हितग्राही योजना का लाभ उठा कर फूलों से बनने वाले उत्पादों से जुड़े हुए है।

मंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रदर्शनी बहु-उद्देशीय है

- फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देकर कृषकों की आय में वृद्धि करना।
- विभिन्न प्रजातियों में फूलों के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
- कृषकों को नवीन तकनीकों, उन्नत किस्मों एवं आधुनिक उत्पादन विधियों से जोड़कर उन्हें प्रोत्साहित करना।
- पुष्प उत्पादन एवं शोभायमान पौधों का उत्पादन करने वाली नर्सरियों को बढ़ावा देना।
- शहरी क्षेत्रों में शोभायमान वाटिकाओं, उद्यानों एवं हरित परिवेश के प्रति नागरिकों की रुचि विकसित करना।
- आमजन में पर्यावरण संरक्षण, हरित जीवनशैली एवं उद्यानिकी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

पुष्प प्रदर्शनी के प्रमुख आकर्षण

पुष्पों एवं प्रसंस्कृत उत्पादों का भव्य प्रदर्शनमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में उत्पादित दुर्लभ, आकर्षक एवं रंग-बिरंगी पुष्प प्रजातियों तथा पुष्पों से निर्मित प्रसंस्कृत उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे।

अवैध पटाखा फैक्ट्री में भरा था 2 टन बारूद

पुलिस बोली- कांग्रेस नेता चला रहा था; विस्फोटक शिफ्ट करने की तैयारी थी

खंडवा (नप्र)। खंडवा पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से करीब दो टन बारूद और रस्सियां मिली हैं।

एसपी मनोज कुमार राय ने कहा- अवैध फैक्ट्री सम्यक गोल्ड कॉलोनी के क्लब हाउस की छत पर चलाई जा रही थी। पुलिस जिस वक्त वहां पहुंची, विस्फोटक शिफ्ट करने की तैयारी चल रही थी। मौके

पर एक पिकअप वाहन खड़ा था। उसके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया है कि फैक्ट्री यूथ कांग्रेस में पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर इमरान परयानी की है।

सुनसान कॉलोनी में चला रहे थे फैक्ट्री

एसपी ने कहा- यह कॉलोनी करीब 15 साल पहले पूर्व मंत्री हीरालाल सिलावट की जमीन पर काटी गई थी। उस समय इसे हाईटेक स्तर पर डेवलप किया गया था, लेकिन फिलहाल यह खंडहर हालत में है। कॉलोनी में बिजली लाइन तक नहीं है। सूनेपन का फायदा उठाकर यहां अवैध रूप से विस्फोटक जमा कर पटाखे बनाए जा रहे थे।

एमपी के गुना-बड़वानी, धार और मुरैना में बारिश

- भोपाल-ग्वालियर समेत 28 जिलों में अलर्ट; दो दिन बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मंगलवार को गुना, बड़वानी, धार के मनावर और मुरैना में मावठा गिरा। मौसम विभाग ने भोपाल-ग्वालियर समेत 28 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) और ट्रफ की वजह से हो रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा एवं आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवात सक्रिय है। यहीं से ट्रफ भी गुजर रही है। मंगलवार से अगले 2 दिन तक एमपी में भी इसका असर रहेगा। कहीं बादल तो कहीं बारिश होने का अनुमान है।

अगले 2 दिन इन जिलों में बारिश- 27 जनवरीः भोपाल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर,

आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, विदिशा, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना।

28 जनवरी : ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, कटनी।

30 जनवरी को नया सिस्टम, फरवरी में भी बारिश- उत्तर-पश्चिम भारत में अगला नया सिस्टम 30 जनवरी को एक्टिव हो रहा है। दो से तीन दिन बाद सिस्टम एमपी में भी असर दिखाएगा। यानी, फरवरी की शुरुआत में भी प्रदेश में बारिश का दौर रह सकता है।

तापमान में गिरावट होगी - बारिश-शीतलहर की वजह से प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने का अनुमान जताया है। इस वजह से कई शहरों में रात का तापमान फिर 10 डिग्री से नीचे आ जाएगा।

संपादकीय

मदर ऑफ डील्स: बड़ी कामयाबी

यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील (एफटीए) मोदी सरकार की बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी है। यह विगत 20 सालों से चली आ रही उतार-चढ़ाव भरी वार्ताओं का नतीजा है, लेकिन तात्कालिक तौर पर इसका बहुत कुछ श्रेय तो अमेरिका के मनमौजी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देना पड़ेगा, जिनके टैरिफ वार से परेशान यूरोप ने भारत जैसे बड़े बाजार वाले देश के साथ यह समझौता किया है। इस समझौते का पूरी दुनिया में संदेश गया है। यूरोपीय बाजारों में भारत की पैठ निश्चित रूप से चीन को भी झटका देगी, क्योंकि चीन ने वहां बहुत पहले घुसपैठ कर ली है। इस समझौते को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' इसलिए कहा जा रहा है कि एक झटके में भारत ने यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ यह समझौता कर लिया है। निश्चित रूप से इसका श्रेय यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा तथा यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सला वान डेर लायेन को जाता है। भारत ने भी उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाकर गदगद कर दिया। हालांकि यह अहम समझौता तत्काल लागू नहीं होगा। इसका यूरोपीय यूनियन के सभी देश वैधानिक रूप से अनुमोदन करेंगे। इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से भारत के व्यापार क्षेत्र में यह नई और महत्वपूर्ण शुरूआत है। इस डील की घोषणा के समय बोलते हुए कहा कि आज 27 तारीख है और ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ने ये एफ़टीए किया है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के क़रीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के क़रीब वन थर्ड हिस्से को रिप्रजेंट करता है। पीएम ने दावा किया कि इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को 'मज़बूती मिलेगी। इस समझौते से टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, लेदर एंड शूज़, जैसे सेक्टर को फ़ायदा होगा। सरकार ने उम्मीद जताई कि इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा और सर्विसेज़ से जुड़े सेक्टर का भी विस्तार होगा। साथ ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिज़नेस, हर इन्वेस्टर के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मज़बूत करेगा।

वहीं एंटोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा ने कहा कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। ऐसे में भारत और यूरोप के बीच ये साझेदारी ऐतिहासिक है। भारत हमारे भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर आगे आया है। इस डील से दो अरब लोगों का फ़ायदा होगा। वहीं यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है। हमारी रिलेशनशिप आगे और भी मज़बूत होगी। दावा है कि इस समझौते से भारत और यूरोपीय देशों को समान से रूप से फायदा होगा। कितना होगा, यह आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि भारत को अगर यूरोपीय देशों का पचास करोड़ रू. का बाजार मिलेगा तो यूरोपीय देशों को भारत का डेढ़ सौ करोड़ लोगों का बाजार मिलेगा, जिसमें पचास करोड़ वो लोग हैं, जो मध्यमवर्गीय हैं। समझौते के तहत या तो भारतीय सामानों पर यूरोपीय टैरिफ पूरी तरह खत्म होगा या फिर बहुत ही कम होगा। बताया जाता है कि ईयू के साथ समझौते में भी इस बात का ख्याल रखा गया है कि भारत का डेयरी और कृषि क्षेत्र अप्रभावित रहे। पीएम मोदी ने कहा कि इस सौदे में भारत से निर्यात किए जाने वाली 9425 टैरिफ़ लाइन को ख़त्म कर दिया गया है। भारत से यूरोप को 6.41 लाख करोड़ का सामान निर्यात किए जाने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि साल 2024-25 में भारत और ईयू के बीच सामान का व्यापार क़रीब 11.5 लाख करोड़ रुपये का रहा, जबकि सेवाओं का व्यापार 7.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

इक्कीसवीं सदी में निराशा के नए कर्तव्य

नजरिया

अरुण कुमार त्रिपाठी
लेखक स्तंभकार और मीडिया शिक्षक हैं।

चौंसठ साल पहले डॉ. राम मनोहर लोहिया ने नैनीताल में 23 जून 1962 को एक व्याख्यान दिया था, जिसका शीर्षक था 'निराशा के कर्तव्य'। उनका कहना था कि उन्हें काफी समय से तीन तरह की निराशा है। एक राष्ट्रीय निराशा, दूसरी अंतरराष्ट्रीय निराशा और तीसरी मानवी निराशा। उनके इस व्याख्यान को आज नए सिरे से पढ़ने और उसकी नए संदर्भों में व्याख्या करने की आवश्यकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में जिस तरह अमेरिकी साम्राज्यवाद का डंका बजाना शुरू कर दिया है उसे देख कर लगता है कि अंतरराष्ट्रीय निराशा ज्यादा प्रबल है। हमें पहले उसी से लड़ना और सोचना चाहिए। लेकिन अपने देश में अधिनायकवाद, घृणा और नागरिक अधिकारों का दमन जिस पैमाने पर हो रहा है उसे देखकर लगता है कि इसी से लड़ना जरूरी है। तीसरी निराशा मानव के स्वभाव को लेकर है। उसके भीतर करुणा, बंधुत्व, बराबरी और स्वतंत्रता की भावना का जिस तरह से लोप होता गया है उससे तो लगता है पहले उसी को जगाया जाना चाहिए।

यह दुविधा पिछली सदी में भी थी और इस सदी में भी है कि हमें अन्यायी ताकतों के आगे झुककर अपना काम निकालना चाहिए या उसका प्रतिरोध करके उससे लड़ना चाहिए। भारत में बीसवीं सदी में भी वैसी शक्तियां थीं जो कहती थीं कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक सत्ता से टकराने से कुछ नहीं होगा। वे बहुत न्यायप्रिय हैं और जो देते जाएं उसे लेते जाना चाहिए। संयोग से वे शक्तियां आज भारत में सत्ता में हैं। पाकिस्तान में सत्ता में हैं और बांग्लादेश में भी वैसी ही ताकतें सत्ता में आने की राह देख रही हैं। इसलिए आज अगर भारत सरकार का नेतृत्व वेनेजुएला की संप्रभुता पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने का विरोध नहीं करता तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वह ईरान में खुमैनी की सत्ता के विरोध में चल रहे प्रदर्शन और उसमें अमेरिका और इजराइल के हस्तक्षेप पर कुछ नहीं बोलता इस पर आश्चर्य नहीं होता। वह सरकार जो राष्ट्र के आर्थिक हितों के आधार पर विदेश नीति बनाने का दावा करती है वह बिना कुछ बताए ईरान के चाबहार बंदरगाह से अपने को बाहर लेती है और भारत के हजार करोड़ रुपए के निवेश को डूब जाने देती है इस पर अवश्य आश्चर्य होता है। हालांकि सरकार इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कह रही है।

भारत से बेहतर तो वे युरोपीय देश हैं जो डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड को अमेरिका द्वारा हथियाए जाने का विरोध कर रहे हैं। बर्फीली ठंड में भी ग्रीनलैंड के राजनैतिक दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि वे अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एक सर्वे में ग्रीनलैंड के 85 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि वे अमेरिका में जाने के विरुद्ध हैं। जबकि 6 फीसदी लोग अमेरिका में मिलना चाहते हैं। यूरोपीय संघ के देश जो नाटो के भी सदस्य हैं उनमें डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन नीदरलैंड यूनाइटेड किंगडम सभी अमेरिका के इस प्रयास के विरुद्ध हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति

इमैनुअल मैक्रां ने कहा है कि उन पर किसी भी तरह की धमकी का असर नहीं होगा। न ही ग्रीनलैंड के मामले में और न ही यूक्रेन के मामले में। युरोपीय संघ अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामेर ने तो और भी सख्त बयान जारी किया है कि ऐसा कदम पूरी तरह से गलत है। यूरोपीय संघ ने कहा कि इस मामले में शुल्क लगाने से अमेरिका भी गरीब होगा और यूरोपीय संघ भी। नाटो तो टूटेगा ही। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने इरादे पर कायम हैं और कह रहे हैं कि यूरोप के आठ देश ग्रीनलैंड की यात्रा पर जाकर खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अमेरिका तो 150 वर्षों से ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है।

इन सबसे ज्यादा विडंबना यह है कि भारत में व्यापक मध्यवर्ग इन घटनाओं का मजा ले रहा है। उसके मन में युद्ध की हिंसा और शक्ति के दमनकारी कृत्यों के प्रति भय और चिंता नहीं गजब का आकर्षण है। वह जिस तरह से अपने देश में विपक्षी दलों, अल्पसंख्यकों और किसानों, मजदूरों के दमन के प्रति उदासीन ही नहीं समर्थन में खड़ा रहता है उसी तरह से वह दुनिया में फैल रही अंतरराष्ट्रीय अराजकता और दुर्व्यवस्था के प्रति रोमांच का भाव पाले हुए है। यह वही वर्ग है जो देश या दुनिया में अन्याय के विरोध में लड़ने वालों को आंदोलनजीवी मानता है और चाहता है कि सरकारें उसे कुचल दें ताकि देश दुनिया में शांति रहे। यह तबका आजादी के बाद देश में अन्याय के विरुद्ध हुए तमाम आंदोलनों को गैर जरूरी मानता है और कभी कभी तो आजादी के पहले के भी आंदोलनों को गैर जरूरी मानता है। उसका मानना है कि गांधीजी अधिक आंदोलन करते थे, इसीलिए मुस्लिम लीग और उसके नेता जिन्ना ने उनसे किनारा करके अलग देश मांगा और गांधी से नाराज अंग्रेजों ने उन्हें वह दे दिया।

ऐसे में सवाल यह है कि किया क्या जाए? एक तरीका तो यह है कि दुनिया में संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान करने वाली जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनी थी उसकी रक्षा की जाए। ट्रंप के नए साम्राज्यवादी रवैए से जो देश परेशान हैं वे पहल करके संयुक्त राष्ट्र जैसा ही कोई नया संगठन बना सकते हैं। युरोप में जो सरकारें ट्रंप के खिलाफ गोलबंद हो रही हैं वे अपनी गोलबंदी को दिखावटी न रहने दें बल्कि उसे ताकत प्रदान करें। लेकिन इसके लिए उन्हें रूस और चीन जैसा विस्तारवादी वर्ताव छोड़ना होगा। रूस को युक्रेन पर हमला रोकना और उसकी कब्जा की गई जमीनें वापस करनी होंगी। लेकिन यह संघर्ष ईरान में जमा हुआ खुमैनीवाद कर पाएगा इसमें संदेह है। हालांकि इसमें संदेह नहीं कि खुमैनीवाद ने भारत में उभर रहे हिंदुत्व के मुकाबले अधिक साम्राज्यवाद विरोधी चरित्र प्रदर्शित किया है। पर उसकी कट्टरता और अपने नागरिकों पर अत्याचार करने की परंपरा डराती है।

दूसरा तरीका पूरी दुनिया में बची खुली कम्युनिस्ट और समाजवादी ताकतों को एकजुट करके प्रतिरोध की नई ताकत खड़ी करने का है। आज भी साम्राज्यवाद के विरुद्ध देश में समाजवादी ताकतों ने ही प्रतिरोध किया है। उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां और ट्रेड यूनियन संगठन शामिल हैं। तीसरा तरीका वह है जो गांधी ने सुझाया था। वह तरीका लंबा है लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि इक्कीसवीं सदी न तो उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की तरह सुस्ती से चलने वाली है और न ही उसका गांधी मोहनदास कर्मचंद जैसा होगा। गांधी का संघर्ष केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं था। वह हर किस्म के अन्याय के विरुद्ध था। वह यह नहीं चाहते कि अमेरिका और इजराइल का सैनिक आतंक मिटे और अयातुल्ला खामेनी के सुरक्षा बलों का आतंक कायम हो। इसलिए यह कहना उचित है कि गांधी सिर्फ भारत की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे बल्कि वे ब्रिटेन को भी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दिला रहे थे। उस लिहाज से भारत ही नहीं युरोप और अमेरिका को भी इक्कीसवीं सदी के लिए कोई गांधी चाहिए। ध्यान रहे गांधी कोई अलौकिक और असंभव व्यक्तित्व नहीं थे।

यहां पर डॉ. लोहिया के उस कथन का उल्लेख करना आवश्यक है जो वे तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के सत्ताधारियों के बहाने कहते थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि गांधी का काम था अंग्रेजी राज को खत्म करना और हिंदुस्तान को आजाद कराना। इसके अलावा वे गांधी की बातों को एक अद्भुत और अलौकिक व्यक्ति की बातें बताकर यह साबित कर देते हैं कि वैसा काम तो गांधी कर सकते थे और अब वे आने वाले नहीं। निश्चित तौर पर देश और दुनिया को इस तर्क प्रणाली से बाहर निकलना होगा।

इससे भी बड़ी बात है अच्छाई को पहचानना और उसके प्रेरणा स्रोत की तलाश करना। वह कहां मिलेगी? वह कैसे मिलेगी? निश्चित तौर पर वह मानव की चिंतन प्रणाली में मिलेगी, उसके डीएनए में मिलेगी और उसके लिए तीव्र गति से भागने और मिसाइलों के प्रयोग से बाहर निकलकर धीमी गति से सोचना और कार्य करना होगा। उसमें मानव का कल्याण, उसकी भावी पीढ़ियों का कल्याण और इस ग्रह और उसके तमाम जीव जंतुओं के कल्याण के बारे में सोचना होगा। निराशा के इस नए कर्तव्य के तौर पर हमें एक नैतिक आख्यान खड़ा करना होगा और उसके वाहक नैतिक साहस वाले मनुष्य तैयार करने होंगे। लोहिया को उम्मीद थी कि बीसवीं सदी के खत्म होने तक मनुष्य गैर बराबरी और नाइंसाफी से मुक्त हो जाएगा। हम उनके सपने को विफल न मानते हुए फिर से इस सदी में देख सकते हैं और ऐसा करने में किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए।

प्रजातंत्र को वास्तविक गणतंत्र में बदलने की जरूरत

गणतंत्र दिवस

प्रो.संजय द्विवेदी
अध्यक्ष, जनसंचार विभाग, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विवि, भोपाल

आजादी के लगभग 8 दशक पूरे करने के बाद भारतीय गणतंत्र एक ऐसे मुकाम पर है, जहाँ से उसे सिर्फ आगे ही जाना है। अपनी एकता, अखंडता और सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के साथ पूरी हुई इन 8 दशकों की यात्रा ने पूरी दुनिया के मन में भारत के लिए एक आदर पैदा किया है। यही कारण है कि हमारे भारतवंशी आज दुनिया के हर देश में एक नई निगाह से देखे जा रहे हैं। उनकी प्रतिभा का आदर और मूल्य भी उन्हें मिल रहा है। हमें सोचना होगा कि आखिर हम उस सपने को कैसा पूरा कर सकते हैं जिसे पूरे करने के लिए सिर्फ कुछ साल बचे हैं। यानि 2047 में भारत को महाशक्ति और विश्वगुरु बनाने का सपना। आजादी के लड़ाई के मूल्य आज भले थोड़ा धुंधले दिखते हों या राष्ट्रीय पर्व औपचारिकताओं में लिपटे हुए, लेकिन यह सच है कि देश की युवाशक्ति आज भी अपने राष्ट्र को उसी ज़ज्बे से प्यार करती है, जो सपना हमारे सेनानियों ने देखा था। आजादी की जंग में जिन नौजवानों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, वही ललक और प्रेरणा आज भी भारत के उत्थान के लिए नई पीढ़ी में दिखती है। हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र में भले ही संवेदना घट चली हो, लेकिन आम आदमी आज भी बेहद ईमानदार और नैतिक है। वह सीधे रास्ते चलकर प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है। यदि ऐसा न होता तो विदेशों में जाकर भारत के युवा सफलताओं के इतिहास न लिख रहे होते। जो विदेशों में गए हैं, उनके सामने यदि अपने देश में ही विकास के समान अवसर उपलब्ध होते तो वे शायद अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए प्रेरित न होते। बावजूद इसके विदेशों में जाकर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और ईमानदारी से भारत के लिए एक ब्रांड एंबेसेडर का काम किया है। यही कारण है कि साँप, सपेरों और साधुओं के रूप में पहचाने जाने वाले भारत की छवि आज एक ऐसे तेजी से प्रगति करते राष्ट्र के रूप में बनी है, जो तेजी से अपने को एक महाशक्ति में बदल रहा है। आर्थिक सुधारों की तीव्र गति ने भारत को दुनिया के सामने एक ऐसे चमकीले क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है, जहाँ व्यवसायिक विकास की भारी संभावनाएं देखी जा रही हैं। यह अकारण नहीं है कि तेजी के साथ भारत की तरफ विदेशी राष्ट्र आकर्षित हुए हैं। बाजारवाद के हो-हल्ले के बावजूद आम भारतीय की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में व्यापक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। ये परिवर्तन आज भले ही मध्यवर्ग तक सीमित दिखते हों, इनका लाभ आने वाले समय में नीचे तक पहुँचेगा।

आकांक्षावान भारत का उदय: भारी संख्या में युवा शक्तियों से सुसज्जित देश अपनी आंकाक्षाओं की पूर्ति के लिए अब किसी भी सीमा को तोड़ने को आतुर है। युवाशक्ति तेजी के साथ नए-नए विषयों पर काम कर रही है, जिसने हर क्षेत्र में एक ऐसी प्रयोगधर्मी और प्रगतिशील पीढ़ी खड़ी की है, जिस पर दुनिया विस्मित है। सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्में, कृषि और अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों या विविध प्रदर्शन कलाएँ हर जगह भारतीय प्रतिभाएँ वैश्विक संदर्भ में अपनी जगह बना रही हैं। शायद यही कारण है कि भारत की तरफ देखने का दुनिया का नजरिया पिछले एक दशक में बहुत बदला है। ये चीजें अनायास और अचानक घट गई हैं, ऐसा भी नहीं है। देश के नेतृत्व के साथ-साथ आम आदमी के अंदर पैदा हुए आत्मविश्वास ने विकास की गति बहुत बढ़ा दी है। भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की तमाम कहानियों के बीच भी विश्वास के बीज धीरे-धीरे एक वृक्ष का रूप ले रहे हैं।

कई स्तरों पर बंटे समाज में भाषा, जाति, धर्म और प्रांतवाद की तमाम दीवारें हैं। कई दीवारें ऐसी भी कि जिन्हें हमने खुद खड़ा किया है और हमारा बुरा सोचने वाली ताकतें उन्हें संबल दे रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर भी जब देश बँटा हुआ नज़र आता है, तो कई बार आम भारतीय का दुख बढ़ जाता है। घुसपैठ की समस्या भी एक ऐसी समस्या है जिससे लगातार नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। किसी तरह भी वोट बैंक बनाने और सत्ता हासिल करने की होड ने तमाम मूल्यों को शीर्षासन करा दिया है। ऐसे में जनता के विश्वास की रक्षा कैसे की जा सकती है? आजादी के इतने साल के बाद लगभग वही सवाल आज भी खड़े हैं, जिनके चलते देश का बँटवारा हुआ और महात्मा गांधी जैसी विभूतियां भी इस बँटवारे को रोक नहीं पाई। देश के अनेक हिस्सों में चल रहे अतिवादी आंदोलन, चाहे वे किसी नाम से भी चलाए जा रहे हों या किसी भी विचारधारा से प्रेरित हों। सबका उद्देश्य भारत की प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकाना ही है। अनेक विकास परियोजनाओं के खिलाफ इनका हस्तक्षेप यह बताता है कि सारा कुछ बेहतर नहीं है। गणतंत्र को सार्थक करने के लिए हमें साधन संपन्नों और हाशिये पर खड़े लोगों को एक तल पर देखना होगा। क्योंकि आजादी तभी सार्थक है, जब वह हिंदुस्तान के हर आदमी को समान विकास के अवसर उपलब्ध कराए। कानून की नजर में हर आदमी समान है, यह बात नारे में नहीं, व्यवहार में भी दिखनी चाहिए।

अंतिम आदमी का कीजिए विचार- गणतंत्र के बारे में कहा जाता है कि वह सौ सालों में साकार होता है। भारत ने इस यात्रा की भी काफी यात्रा पूरी कर ली है। बावजूद इसके हमें डॉ. राममनोहर लोहिया की यह बात ध्यान रखनी होगी कि 'लोकराज लोकलाज से चलता है।' इसी के साथ याद आते हैं पं. दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग, जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन देकर भारतीय राजनीति को एक ऐसी दृष्टि दी है, जिसमें आम आदमी के लिए जगह है। यह दर्शन हमें दरिद्रनारायण की सेवा की मार्ग पर प्रशस्त करता है। महात्मा गांधी भी अंतिम व्यक्ति का विचार करते हुए उसके लिए इस तंत्र में जगह बनाने की बात करते हैं। हमें सोचना होगा कि गणतंत्र के इन वर्षों में उस आखिरी आदमी के लिए हम कितनी जगह और कितनी संवेदना बना पाए हैं। प्रगति और विकास के सूचकांक तभी सार्थक हैं, जब वे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने में समर्थ हों। क्या ऐसा कुछ बताने और कहने के लिए हमारे पास है? यदि नहीं...तो अभी भी समय है भारत को महाशक्ति बनाना है, तो वह हर भारतीय की भागीदारी से ही सच होने वाला सपना है। देश के तमाम वंचित लोगों को छोड़कर हम अपने सपनों को सच नहीं कर सकते। क्या हम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं।

तलाशिए सवालों के जवाब: गणतंत्र दिवस इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है। बीते समय में आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रीयता की तमाम गंभीर चुनौतियों के सामने हमारा तंत्र बहुत बेबस दिखा। बावजूद इसके लोकतंत्र में जनता की आस्था बची और बनी हुयी है। हमारी एकता को तोड़ने और मन को तोड़ने के तमाम प्रयासों के बावजूद आम हिंदुस्तानी अपनी समूची निष्ठा से इस देश को एक देखना चाहता है। यह संकल्प लेना होगा कि हम लोकतंत्र में लोगों के भरोसे को जगा पाएं। उनकी उम्मीदों पर अवसाद की परतें न चढ़ने दें। सपनों में रंग भरने की हिम्मत, ताकत और जोश से भरा हो- आम हिंदुस्तानी तो इसी सपने को सच होते हुए देखना चाहता है। यह संयोग ही है कि नया साल और गणतंत्र दिवस हम एक ही महीने जनवरी में मनाते हैं। जाहिर तौर पर हर नए साल का मतलब कलैंडर का बदलना भर नहीं है वह उत्सव है संकल्प का, अपने गणतंत्र में तेज भरने का। आम आदमी में जो भरोसा टूटता दिखता है उसे जोड़ने का। गणतंत्र को तोड़ने या कमजोर करने में लगी ताकतों के मंसूबों पर पानी फेरने का। जनवरी का महीना इसीलिए बहुत खास है क्योंकि यह महीना देश की अस्मिता को पहली बार झकझोर कर जगाने वाले सन्यासी विवेकानंद की जन्मतिथि (12 जनवरी) का महीना है। जिन्होंने पहली बार भारत के दर्शन को विश्वमंच पर मान्यता ही नहीं दिलायी हमारे दबे-कुचले आत्मविश्वास को जागृत किया। यह महीना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन (23 जनवरी) का जिन्होंने विदेशी सत्ता के दांत खट्टे कर दिए और विदेशी भूमि पर भारतीयों के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी सेना खड़ी की। जाहिर तौर पर यह महीना सही संकल्पों और महानायकों की याद का महीना है। इससे हमें प्रेरणा लेने और आगे बढ़ने की जरूरत है। नए साल का सूरज हमें एक नयी रोशनी दे रहा है उसका उजास हमें नई दृष्टि दे रहा है। क्या हम इस रोशनी से सबक लेकर, अपने महानायकों की याद को बचाने और देश को महाशक्ति बनाने के सपने के साथ खड़ा होने का हौसला दिखाएंगें?

शिक्षक विहीन स्कूल पर हाई कोर्ट नाराज

शिक्षा

संदीप कुलश्रेष्ठ
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

मध्यप्रदेश के डिंडोरी निवासी लोकसिंह की जनहित याचिका पर हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति और शिक्षकों की भारी कमी को लेकर सख्त रूख अपनाया है। चीफ जस्टिस श्री संजीव सचदेवा और जस्टिस श्री विनय सराफ की पीठ ने राज्य सरकार से मध्यप्रदेश के स्कूलों और शिक्षकों की जानकारी तलब की है।

हाई कोर्ट को जनहित याचिका में बताया गया है कि अकेले डिंडोरी जिले में ही 102 स्कूल ऐसे हैं, जिसमें एक भी शिक्षक है ही नहीं। इसके साथ ही जबलपुर में 54 स्कूल ऐसे हैं, जो शिक्षकों की कमी के कारण बंद होने की कगार पर है। याचिकाकर्ता ने इसे शिक्षा के अधिकार नियम का उल्लंघन बताया है।

मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह दावे केवल कागजों की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 46 जिलों में 1275 स्कूल ऐसे हैं, जिनमें एक भी शिक्षक नहीं है। 22 हजार स्कूलों में महज एक-एक शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही है। साढ़े तीन हजार स्कूल ऐसे भी हैं, जहां एक भी बच्चा नहीं है।

मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने सीएम राईज स्कूल की शुरुआत की है। यह स्कूल सुविधाओं से युक्त है। इन स्कूलों में बच्चों को आने-जाने के लिए निःशुल्क बस सुविधा भी उपलब्ध की है।

प्रदेश में माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के करीब 79 हजार पद खाली हैं। हालांकि इस साल 9 हजार पदों पर भर्ती होने के बाद भी करीब 70 हजार पद खाली रह जाएंगे। इसका सीधा असर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर देखें तो शहरों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों की भरमार है तो गांवों में टोटा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गांवों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

शौचालय विहिन 20 प्रतिशत स्कूल – प्रदेश में 20 प्रतिशत स्कूल शौचालयविहिन है। जहां शौचालय है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 35.9 प्रतिशत शौचालयों का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। 28.4 प्रतिशत स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं है। इसी राज्य प्रदेश के 5176 स्कूलों में पेयजल के इंतजाम नहीं है। 44 हजार 754 स्कूलों में खेल मैदान का अभाव है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से अपेक्षा है कि वे मध्यप्रदेश के ऐसे सभी शिक्षक विहीन स्कूलों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों की तैनाती करें, ताकि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। इसके साथ ही ऐसे स्कूलों में जहां एक से पांचवी कक्षा तक केवल एक शिक्षक है, वहां कम से कम दो शिक्षकों की तैनाती करे। इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के मान से पर्याप्त शिक्षक तैनात करे, ताकि बच्चे की नीवं मजबूत बन सके।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

देश तो चल ही रहा है... घर भी तो चल ही रहा है

व्यंग्य

सचिन सिंह परिहार
लेखक राष्ट्रीय कराते खिलाड़ी हैं।

26 जनवरी छोटे कस्बों में आते ही देशभक्ति को लाउडस्पीकर मिल जाता है। सुबह-सुबह तहसील मैदान से राष्ट्रगान की आवाज़ गूँजने लगती है। आवाज़ थोड़ी कर्कश होती है, बीच-बीच में माइक फँस भी जाता है, लेकिन भावना में कोई कमी नहीं रहती। चौराहे पर तिरंगा लहरा रहा होता है और दो पुलिसवाले ऐसे खड़े होते हैं मानो पूरे गणतंत्र की सुरक्षा उन्हीं के कंधों पर टिकी हो। कस्बे में गणतंत्र दिवस सिर्फ़ सरकारी कार्यक्रम नहीं होता, बल्कि घर-घर चलने वाला एक घरेलू लोकतंत्र भी होता है।

घर के भीतर सबसे पहले अपनी नागरिकता का ऐलान करता है घर का सबसे छोटा नागरिक। वह पूरे आत्मविश्वास से कहता है, 'आज स्कूल नहीं है।'

उसके लिए 26 जनवरी किसी राष्ट्रीय पर्व से ज़्यादा लंबी नींद की योजना है। न यूनिफ़ॉर्म, न टिफ़िन, न सुबह की हड़बड़ी। उसके चेहरे पर ऐसा गर्व होता है मानो संविधान की प्रस्तावना उसी ने लिखी हो। उसके लोकतंत्र में छुट्टी का मतलब होता है पूरी आज़ादी। लेकिन यहीं से घरेलू संविधान की असली धाराएँ सामने आती हैं।

मम्मी बिना किसी भाषण के कह देती हैं, 'स्कूल की छुट्टी है, काम की नहीं।' बच्चा पहली बार समझता है कि छुट्टी भी शर्तों के साथ आती है। कस्बाई लोकतंत्र में बच्चों की छुट्टी, मम्मियों की ज़िम्मेदारी बढ़ा देती है। झाड़ू, पोछा, सब्ज़ी और रसोई इनका कोई ड्राय डे नहीं होता। अब बारी आती है पापा की, घर के वरिष्ठ नागरिक की। वे अख़बार फैलाकर बैठते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, 'आज छुट्टी है।' यह छुट्टी उन्हें कुछ विशेष अधिकार दे देती है टीवी पर परेड देखने का पहला हक़, सोफ़े पर स्थायी सीट और चाय के कप पर अस्थायी वीटो। अख़बार में वे पढ़ते हैं, 'नगर पालिका कार्यालय में ध्वजारोहण सम्पन्न होगा।' ख़बर पढ़ते ही उन्हें लगता है कि नागरिक कर्तव्य पूरा हो गया। फिर दिन का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 'आज ड्राय डे है।'

ठेका बंद है, शटर आधा गिरा हुआ, मानो दुकान भी राष्ट्र के सम्मान में सिर झुकाए खड़ी हो। पापा एक पल रुकते हैं, फिर गहरी साँस लेकर आगे बढ़ जाते हैं। 'कोई बात नहीं, एक दिन ही तो है।' यह वाक्य त्याग और संयम का प्रतीक बन जाता है। मम्मी इस सबको चुपचाप देखती हैं। उनके लिए 26 जनवरी का मतलब होता है 'आज कोई भी आ सकता है।' कस्बे में रिश्तेदार कभी दूर नहीं होते। 'बस झंडा देखने निकले थे' कहकर दोपहर में हाज़िर हो सकते हैं। इसलिए रसोई में तैयारी ज़्यादा रहती है दाल थोड़ी अतिरिक्त, रोटियाँ गिनकर और मिठाई 'अगर मेहमान आ जाएँ' वाले कोटे में।

शाम होते-होते कस्बा शांत हो जाता है। लाउडस्पीकर बंद हो जाते हैं, मैदान खाली हो जाता है और घरों में टीवी पर दिल्ली की परेड चलती है। बाहर तिरंगे हवा में हिलते रहते हैं और भीतर चाय के कपों से देशभक्ति की भाप उठती रहती है।26 जनवरी यहाँ सिर्फ़ राष्ट्रीय पर्व नहीं रहता, बल्कि घरेलू लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण बन जाता है जहाँ बच्चों को छुट्टी का अधिकार, मम्मियों को ज़िम्मेदारी का भार और पापाओं को ड्राय डे का अनुशासन मिलता है।

शाम के बाद टीवी रिमोट को लेकर बहस शुरू होती है। पापा न्यूज़ चैनल लगाते हैं, बच्चा कार्टून चाहता है। मम्मी बीच में बैठकर फ़ैसला सुनाती हैं पहले न्यूज़, फिर कार्टून। यह घरेलू सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश होता है। पड़ोस में कहीं अब भी 'विजयी विश्व तिरंगा प्यारा' बज रहा होता है। कस्बे में देशभक्ति देर से जाती है कुछ लोग अब भी तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे होते हैं।

गली के कोने की चाय की दुकान खुल जाती है। ड्राय डे के कारण वहाँ आज संयम है। लोग चाय के साथ संविधान, भ्रष्टाचार और क्रिकेट पर चर्चा करते हैं। समाधान किसी के पास नहीं, लेकिन बोलना सबको आता है। वहीं एक बुज़ुर्ग मिलते हैं, जो हर साल बताते हैं कि उन्होंने आज़ादी का समय देखा था। तब सब बेहतर था ऐसा उनका विश्वास है। सामने खड़ा युवक वीडियो बनाते हुए सहमति में सिर हिलाता है; उसे भरोसा बातों से ज़्यादा व्यूज़ पर है। बच्चा अपने स्कूल की कविता सुनाने की बात करता है। यह नहीं बताता कि आखिरी पंक्तियाँ उसने खुद बना ली थीं। घर वाले उसकी रचनात्मक स्वतंत्रता की सराहना करते हैं आखिर गणतंत्र यही तो सिखाता है। रात को व्हाट्सऐप पर तिरंगे, जुमले और प्रस्तावना की तस्वीरें घूमने लगती हैं। भावना लेखक से बड़ी मानी जाती है। सोने से पहले पापा कहते हैं, 'देश तो चल ही रहा है।' 'मम्मी जवाब देती हैं, 'घर भी तो चल ही रहा है।' अगले दिन कस्बा फिर सामान्य हो जाता है। स्कूल खुलते हैं, दफ़्तरों में फाइलें लौट आती हैं और ठेके का शटर पूरा उठ जाता है। कुछ घरों पर तिरंगे अब भी लगे रहते हैं थोड़े थके हुए, लेकिन गर्व से भरे। और शायद यही 26 जनवरी की खासियत है। यह एक दिन के लिए हमें रोकता है सोचने के लिए। देश के लोकतंत्र पर भी, और घर के लोकतंत्र पर भी।

कस्बे जानते हैं कि लोकतंत्र कोई आदर्श नहीं, बल्कि रोज़ निभाई जाने वाली प्रक्रिया है कभी छुट्टी, कभी ड्यूटी और कभी संयम के रूप में। इसीलिए 26 जनवरी उनके लिए सिर्फ़ तारीख़ नहीं, एक अभ्यास है। क्योंकि असली गणतंत्र वही होता है, जो सरकारी मैदान से निकलकर रसोई, चाय की दुकान और बच्चों की छुट्टी तक पहुँच सके। और छोटे कस्बे यही काम बख़ूबी करते हैं।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

भगवद् गीता पढ़ाना धार्मिक कृत्य नहीं

भगवद् गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है। यह एक नैतिक विज्ञान है। इसलिए भगवद् गीता को किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है। मंत्रालय ने तर्क दिया था कि ट्रस्ट का फोकस भगवद् गीता, उपनिषद, वेदांत और संस्कृत पढ़ाने पर है, इसलिए यह एक धार्मिक संगठन है। जबकि, उच्च न्यायालय ने मंत्रालय के इस विचार को खारिज कर दिया कि वेदांत, संस्कृत और योग सिखाने से ट्रस्ट एक धार्मिक संस्था बन जाता है। न्यायालय ने कहा कि वेदांत एक दार्शनिक प्रणाली है। यह योग कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक अभ्यास है। केवल ऐसी शिक्षाएं देने से कोई संगठन धार्मिक नहीं बन जाता।

मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में दिए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि वेदांत, संस्कृत और योग सिखाने से ट्रस्ट एक धार्मिक संगठन नहीं बन जाता है। न्यायालय ने तीन महीने के भीतर गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 2010 के तहत दी गई अस्वीकृति की नए सिरे से समीक्षा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भगवद् गीता को विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम (एफसीआरए) के मकसद से धार्मिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता। इसलिए, किसी ट्रस्ट को इस आधार पर इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करने से मना नहीं किया जा सकता कि वह गीता और योग सिखाने में शामिल था। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें ''अर्ष विद्या परंपरा ट्रस्ट'' का उक्त अंशदान अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि रजिस्ट्रेशन निरस्ती का आदेश अपर्याप्त, तर्क और प्रक्रियात्मक कमियों पर आधारित था।

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने मंत्रालय को वेदांत शिक्षाओं पर फोकस करने वाले परमार्थ ट्रस्ट द्वारा दिए गए आवेदन पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया। यह ट्रस्ट सन् 2017 में स्थापित था। उक्त ट्रस्ट अर्ष विद्या परंपरा ट्रस्ट वेदांत, संस्कृत और योग सिखाता है। साथ ही प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने का भी काम करता है। ट्रस्ट ने सन् 2021 में उक्त अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया था। लेकिन अनुरोध सालों तक विचाराधीन रहा। गृह मंत्रालय सन् 2024 और सन् 2025 में स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद जनवरी, 2025 में दायर एक नया आवेदन आखिरकार सितंबर 2025 में खारिज कर दिया गया। इसके बाद ट्रस्ट ने इस फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

आवेदन खारिज करने का एक मुख्य कारण मंत्रालय ने यह बताया कि ट्रस्ट धार्मिक लगता है। उच्च न्यायालय ने इस दावे की विस्तार से जांच की। इसमें भगवद् गीता और उसकी शिक्षाओं की प्रकृति के बारे में पिछले न्यायिक टिप्पणियों का हवाला दिया गया था।

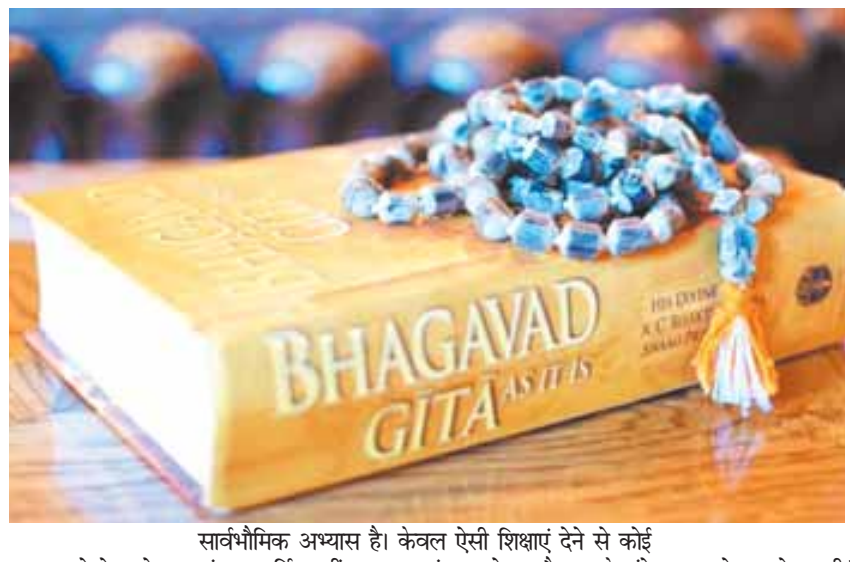

न्यायालय ने कहा कि भगवद् गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है। यह एक नैतिक विज्ञान है। इसलिए भगवद गीता को किसी एक धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा है। मंत्रालय ने तर्क दिया था कि ट्रस्ट का फोकस भगवद् गीता, उपनिषद, वेदांत और संस्कृत पढ़ाने पर है, इसलिए यह एक धार्मिक संगठन है। न्यायालय ने पाया कि यह तर्क उक्त अधिनियम की धारा 11 की जरूरतों को पूरा नहीं करता। यह प्रावधान सांस्कृतिक, शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों वाले समूहों को विदेशी चंदा लेने की अनुमति देता है। लेकिन तभी होगा जब अधिकारी रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले एक निश्चित और अच्छी तरह से समर्थित निष्कर्ष पर पहुँचें। इस जरूरत को समझाते हुए न्यायालय ने कहा कि शब्द निश्चित महत्वपूर्ण है। विवादित आदेश में, दूसरे प्रतिवादी ने यह निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता-संगठन धार्मिक लगता है। धारा में यह कहा गया है कि प्राधिकरण को आवेदक की गतिविधियों के चरित्र के बारे में स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए। यह अस्थायी नहीं हो सकता।

उच्च न्यायालय ने मंत्रालय के इस विचार को भी खारिज कर दिया कि वेदांत, संस्कृत और योग सिखाने से ट्रस्ट एक धार्मिक संस्था बन जाता है। न्यायालय ने कहा कि वेदांत एक दार्शनिक प्रणाली है। यह योग कल्याण के लिए एक सार्वभौमिक अभ्यास है। केवल ऐसी शिक्षाएं देने से कोई संगठन धार्मिक नहीं बन जाता। मंत्रालय ने उस नौ लाख के चंदे की ओर भी इशारा किया। यह ट्रस्ट को एक ऐसे ट्रस्टी से मिला था जो भारत का प्रवासी नागरिक है। इस संबंध में मंत्रालय ने कहा कि यह उक्त अधिनियम एवं नियमों का उल्लंघन है। इसके लिए पहले से मंजूरी नहीं ली गई थी। ट्रस्ट ने गलती स्वीकार की और अधिनियम की धारा 41 के तहत अपराध को कंपाउंड करने का विकल्प चुना। यह कुछ उल्लंघनों को शुल्क देकर निपटाने की अनुमति देता है। न्यायालय ने पाया कि एक बार जब कोई अपराध कंपाउंड हो जाता है, तो बाद में इसे रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता।

न्यायालय ने कहा कि मंत्रालय ने खुद अगस्त, 2025 में कंपाउंडिंग प्रक्रिया पूरी की थी। न्यायालय ने कहा कि जब एक बार अपराध कंपाउंड हो जाता है, तो उल्लंघन कभी भी प्रतिकूल आधार नहीं हो सकता। इसे आवेदक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मंत्रालय को ट्रस्ट को सूचित करना चाहिए था कि कंपाउंडिंग का प्रस्ताव स्वीकार करने से उसके आवेदन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने आगे कहा कि अगर प्राधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज करना चाहती थी, तो प्राधिकारी को कंपाउंडिंग का विकल्प देते समय यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि कंपाउंडिंग केवल उन्हें अभियोजन से बचाएगी। साथ ही यह अपराध स्वीकार करने जैसा होगा जिससे अयोग्यता हो सकती है।

याचिकाकर्ता-न्यास को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत किया गया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने न्यास विलेख की शर्तों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता एक धर्मार्थ संगठन है। न्यायाधिकरण का यह आदेश और याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र सही है। उक्त अधिनियम 2010 में कोई अधिभावी प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर अधिनियम की धारा 52 में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका अपमान नहीं करेंगे। अधिनियम की धारा 52 के अनुरूप प्रावधान अन्य कानूनों में भी पाए जा सकते हैं। उन्हें कुछ निर्णयों में माना गया है। धारा 52 जैसे प्रावधानों का प्रभाव यह है कि अधिनियम में निपटाए गए मामले के संदर्भ में अन्य अधिनियमों को अधिभावी करने का अधिनियम का प्रभाव नहीं है।

यह धारा केवल यह उपबंध करती है कि यह किसी भी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के लाभों का दावा करने के लिए खुला होगा। वह अन्य अधिनियमों के प्रावधानों का भी लाभ उठाएगा, यदि कोई विसंगति या संघर्ष नहीं है। यदि वह कानून के किसी अन्य सिद्धांत जैसे कि रोक या चुनाव द्वारा अन्यथा वर्जित नहीं है। जब आयकर विभाग के अनुसार, याचिकाकर्ता एक धर्मार्थ संगठन है, तो यह उक्त अधिनियम व्यवस्था के तहत एक नहीं रह सकता है। यही अधिनियम की धारा 52 का वास्तविक महत्व है। आयकर अधिनियम की धारा 12-ए के तहत याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र निश्चित रूप से एक प्रासंगिक सामग्री है और उसी पर विचार करने में विफलता दिमाग पर जोर न देने को इंगित करती है।

ट्रस्ट पर एक और आरोप था कि ट्रस्ट ने विदेशी चंदा दूसरे संगठन को ट्रांसफर किया था। यह बात पहली बार सिर्फ अंतिम अस्वीकृति के आदेश में उठाई गई थी। न्यायालय ने कहा कि यह मुद्दा न तो पहले किसी संप्रेषण में उठाया गया और न ही कोई खास जानकारी दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि आखिरी स्टेज पर ट्रस्ट को जवाब देने का मौका दिए बिना नया आरोप लगाना प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय के संबंधित विभाग को ट्रस्ट के आवेदन पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि उनके पास किसी फंड ट्रांसफर का पक्का सबूत है, तो एक नया और विस्तृत सूचना पत्र ट्रस्ट को जारी करें। उच्च न्यायालय ने मंत्रालय को यह प्रक्रिया आदेश मिलने के तीन महीने की अवधि के भीतर पूरी करने को कहा है।

विचार

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ज्ञान-परंपरा से लौटती प्राचीन भारतीय गणतंत्र की गरिमा

**विपक्षी दलों के ऐसे स्थाई भाव के चलते चुनौतियों से निपटना और आजादी के बाद सभी अनुत्तरित रह गए प्रश्नों के व्यावहारिक हल खोजना मुश्किल हो रहा है। फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने धारा-370, 35-ए, तीन तलाक और वक्फ बोर्ड जैसी समस्याओं के हल तलाश कर देश की संप्रभुता की महिमा लौटाई है। राम मंदिर के वैभवशाली पुनर्निमाण ने भारतीयों के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। परंतु अभी भी समान नागरिक संहिता, आबादी नियंत्रण और धर्मांतरण पर अंकुश के स्थायी कानूनी हल स्थापित करना बाकी है। यह विडंबना इसलिए भी है, कि जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहे थे, तब वे अभावग्रस्त और कम पढ़े-लिखे होने के बावजूद अपने पारंपरिक ज्ञान और चेतना से इतने बौद्धिक थे कि किसान-मजदूर से लेकर हर उस वर्ग को परस्पर जोड़ रहे थे, जिनका एक-दूसरे के बिना काम चलना मुश्किल हो रहा है। फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने धारा-370, 35-ए, तीन तलाक और वक्फ बोर्ड जैसी समस्याओं के हल तलाश कर देश की संप्रभुता की महिमा लौटाई है। राम मंदिर के वैभवशाली पुनर्निमाण ने भारतीयों के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। परंतु अभी भी समान नागरिक संहिता, आबादी नियंत्रण और धर्मांतरण पर अंकुश के स्थायी कानूनी हल स्थापित करना बाकी है। यह विडंबना इसलिए भी है, कि जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश राज से मुक्ति का आधार बनी। इसीलिए देश के स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय स्वाभिमान की जागृति का संग्राम भी कहा जाता है। राजनीतिक दमन और आर्थिक शोषण के विरुद्ध लोक-चेतना का यह प्रबुद्ध अभियान था। यह चेतना उत्तरोत्तर ऐसी विस्तृत हुई कि समूची दुनिया में उपनिवेशवाद के विरुद्ध मुक्ति का स्वर मुखर हुआ। परिणामस्वरूप भारत की आजादी एशिया और अफ्रीका की भी आजादी लेकर आई। भारत के स्वतंत्रता समर का यह एक वैश्विक आयाम था, जिसे कम ही रेखांकित किया जाता है। इसके वनिस्पत फ्रांस की क्रांति की बात कही जाती है। निसंदेह इसमें समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता के तत्व थे, लेकिन एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की अवाम उपेक्षित थी। अमेरिका ने व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता और सुख के उद्देश्य की परिकल्पना तो की, परंतु इसमें स्त्रियां और हब्शी गुलाम बहिष्कृत रहे। मार्क्स और लेनिनवाद ने एक वैचारिक पैमाना तो दिया, किंतु वह अंततः तानाशाही साम्राज्यवाद का मुखौटा ही साबित हुआ। इस लिहाज से गांधी का ही वह विचार था, जो सम्मगता में भारतीय हितों की चिंता करता था। इसी परिप्रेक्ष्य में दीनदयाल उपध्याय ने एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचार दिए, जो संसाधनों के उपयोग से दूर अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान की चिंता करते हैं।

कमोबेश इन्हीं भावनाओं के अनुरूप डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान को आकार दिया। इसीलिए जब हम सत्तर साल पीछे मुड़कर संवैधानिक उपलब्धियों पर नजर डालते हैं तो संतोष होता है। प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ राष्ट्र-राज्य की व्यवस्थाएं जीवंत हैं। बीच-बीच में आपातकाल जैसी अतिरेक और अराजकता भी दिखाई देती है, लेकिन अंततः मजबूत संवैधानिक व्यवस्था के चलते लंबे समय तक ये स्थितियां गतिशील नहीं रह पाती। फलतः तानाशाही ताकतें स्वयं ही इन पर लगाम लगाने को विवश हुई हैं। यही कारण है कि प्रजातंत्र, समता, न्याय और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ विधि का शासन अनवरत है। भारत की अखंडता और संप्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से सरदार पटेल जैसे लोगों ने कूटनीतिक कड़ाई से 600 से भी ज्यादा रियासतों का विलय कराया। हैदराबाद व जम्मू-कश्मीर रियासतों का विलय हुआ। जमींदारी उन्मूलन व भूमि-सुधार हुए। सर्वोदयी नेता विनोबा भावे ने सामंतों की भूमि को गरीब व वंचितों में बांटने का उल्लेखनीय काम किया। पुर्तगाल और फ्रांस से भी भारतीय भूमि को मुक्त कराया। गोवा आजाद हुआ और सिक्किम का भारत में विलय हुआ।

चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों से सामना किया। इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को विभाजित कर दो देशों में बांटने का दुस्साहसिक कार्य किया। इसी पृष्ठभूमि में गुटनिरपेक्ष व शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व वाली ठोस विदेश नीति अपनाई। विकेंद्रीकरण की नीति अपनाते हुए इंदिरा गांधी ने ही राजाओं के प्रिवीपर्स बंद किए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। देश में औद्योगीकरण की बुनियाद रखने के साथ सामरिक महत्व के इसरो व डीआरडीओ जैसे संस्थान अस्तित्व में आए। इन्हीं की बदौलत हम प्रक्षेपास्त्र और अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने में सक्षम हुए। इस अंतरिक्ष और रक्षा क्रांति को नरेंद्र मोदी ने प्रोत्साहित किया। हरित क्रांति की शुरुआत करके खाद्यान्न के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हुए, बल्कि कृषि उपजों के निर्यात से विदेशी मुद्रा कमाने में भी समर्थ हुए। ये उन्नति के कार्य इसलिए संपन्न हो पाए, क्योंकि 1990 से पहले तक हमारे राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी सही रूप में बौद्धिक होने के साथ स्वदेशी की भावना रखते थे और नैतिक दृष्टि से कमोवेश ईमानदार थे। इसलिए ग्रामों से ज्यादा पलायन नहीं हुआ और खेती-किसानी समृद्ध बने रहे। सरकारी शिक्षा की पाठशालाओं से निकले इस कालखंड के षिक्षित लोग ही श्रेष्ठ वैज्ञानिक अभियंता और चिकित्सक बने। यही नहीं आज हम जिन प्रवासी भारतीयों की बौद्धिक व आर्थिक उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, वह आठवें दशक के अवसान और नौवें दशक के आरंभ की वह पीढ़ी है, जो कनस्तर और बिस्तरबंद के साथ सरकारी विद्यालयों में पढ़कर देश व दुनिया में छा गई थी। बावजूद अंग्रेजी, विदेशी और निजी शिक्षा को सरंक्षण देने की दृष्टि से हमने कई ऐसे नीतिगत उपाय कर दिए, जिससे समूची सरकारी शिक्षा व्यवस्था निराशा और हीनताबोध से ग्रस्त होती चली गई। अब तो प्राथमिक षिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के संस्थान भी छात्रवृत्तियों और मध्यान्य भोजन के बहाने भीख के कटोरों के बूते चल रहे हैं। जबकि यह वही देश है, जहां मिट्टी के द्रोणाचार्य ने एकलव्य से धनुर्धर गढ़े और अर्जुन की सीख ने अभिमन्यू को गर्भ में ही चक्रव्यूह भंग करने में दीक्षित किया। बहरहाल तमाम उपलब्धियों के बीच शिक्षा में ही नहीं सभी क्षेत्रों में नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ। आपातकाल के उपरांत जनता दल की गठबंधन सरकार गिरने के बाद संजय गांधी की युवा-टोली को राजनीति में प्रवेश मिला, उसने मूल्यों के अवमूल्यन की पृष्ठभूमि रची। हाशिए पर पड़े सामंत और जमींदार बड़ी संख्या में एकाएक राजनीति की केंद्रीय भूमिका में आ गए। जब ये विधायक एवं सांसद के रूप में सत्ता-तंत्र में हस्तक्षेप के अधिकारी हुए तो इन्होंने पुनः मृतप्रायः समंती दुष्प्रवृत्तियों को सींचकर हरा-भरा कर लहलहा दिया। स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी के निष्ठावान अनुयायी लगभग निर्वासित कर दिए गए। नतीजतन 1984 में पंजाब में पनपे उग्रवाद के चलते इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो प्रतिकार स्वरूप पूरे देश में कांग्रेसी सत्ता के संरक्षण में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसी की पृष्ठभूमि से भाषाई, जातीय व क्षेत्रीय अस्मिताएं प्रखर आंदोलन के रूप में उभरीं। 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार को देवीलाल ने अस्थिर किया तो उन्होंने मंडल का पिटारा खोल दिया। इसे लेकर मंडल-कमंडल में भी हिंसक टकराव देखने में आए। फलस्वरूप राममनोहर लोहिया के जो अनुयायी भाषाई आंदोलन चला रहे थे, उनकी प्राथमिकता पिछड़ों के जातीय और क्षेत्रीय हितों में जमींदोज हो गई। मुलायम, लालू, शरद, नीतीश और मायावती इन्हीं आंदोलन के अगुआ रहकर मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री बने। यही वह दौर रहा, जिसमें धनबल और बाहुबल का राजनीति में पर्दापण हुआ तथा अपराध का राजनीतिकरण एवं राजनीति का अपराधीकरण हुआ। कांग्रेस और भाजपा भी इससे अछूते नहीं रहे। रही-सही कसर 24 जुलाई 1991 को संरचनागत समायोजन के बहाने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का जो समझौता हुआ, उसने देश की आर्थिक आजादी को लगभग 500 साल के लिए गिरवी रख दिया। नतीजतन हम नव-उपनिवेश के गुलाम होते जा रहे हैं। इन कंपनियों की आवारा पूंजी, पूंजीवाद के विस्तार और प्राकृतिक संपदा की लूट में लगी हुई है। उपभोग की संस्कृति बेलगाम होती जा रही है। इससे मुक्ति विरासत में मिली ज्ञान परंपरा से ही की जा सकती है, जो केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है।

गणतंत्र बोध

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

सबसे अच्छी बात यह है कि भारत निराश नहीं है...

हम भारत के लोगों ने 26 जनवरी कोअ अपने 77 वें गणतंत्र का उत्सव मनाया। यह समय हमें आकलन करने की अपेक्षा करता है कि इतने दीर्घावधि वाले भारत गणतंत्र का 'जन-गन-मन' आज किन अनुभूतियों के साथ जी रहा है। यह आंकलन करने का समय है कि हमारे देश का विकास किस तरह दुनिया को आकर्षित करने लगा है। और यह भी समझना है कि आज भारतीय नागरिक कितना खुश हैं। यह इस देश का सौभाग्य है कि हमारे पास सबसे बड़ी युवा आबादी है। इस देश की महिलाएं विगत 77 वर्षों में पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं से लड़कर मुख्यधारा में सम्मिलित हो चुकी हैं। हमारे देश में पहले की अपेक्षा बाल शिशु मृत्यु दर कम हुई है। हमारे देश में कौशलयुक्त शिक्षा व्यवस्था अपना आकार ले चुकी है और स्टार्टअप के माध्यम से अनेक युवा अपने रोजगार सृजित कर दूसरों को रोजगार देने में सक्षम हुए हैं। यह इस देश की और भारतीय गणतंत्र की खूबसूरती है कि सामाजिक न्याय पहले की अपेक्षा अब ज्यादा दिखने लगा है। एलजीबीटीक्यू ग्रुप, बृद्धजन, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोग और घुमंतू जातियों के लोगों में आत्मसम्मान बढ़ा है। जागरूकता बढ़ी है। लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। जागरूकता का स्तर बढ़ा है। शिक्षा का स्तर बढ़ा है। मानव विकास के सूचकांकों में बृद्धि हुई है। जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। अब किसान की आय में बृद्धि हुई है। हमारे आयत-निर्यात और वैश्विक स्तर पर राजनयिक संबंधों में कभी असहजता जो बढ़ रही थी, उसमें अब सुगमता से डिप्लोमेटिक लेवल पर पॉलिसीज तैयार हुई है। देश ने द्विपक्षीय संबंधों और बहुपक्षीय संबंधों में विश्वास को जीता है और बहुत से देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित हुए हैं।

भारतीय संविधान की यह ताकत है कि भारत गणतंत्र इतना सशक्त व समृद्ध तरीके से अपनी 77 वर्ष का समय पूर्ण करके कई नई पहल करने के लिए सक्षम बन सका है। देश में विशेष संदेश सबके मन के भीतर है कि हम भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था के साथ जीकर 2047 तक विकसित भारतीय गणतंत्र की ओर अग्रसर हों और हमारे भारतीय नागरिकों में स्वबोध, गौरवबोध की स्थापना हो। देसज लोगों के बीच आज जब भारत देखता है तो उनमें से यह आवाज़ आती है कि भारतीय नागरिकों को 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाना है। बिस्मिल अज़ीमाबादी की 'हिकायत-ए-हस्ती' की एक ग़ज़ल है सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और उसमें दो पंक्तियाँ लिखी उन्होंने कि वक़्त आने दे दिखा देंगे तुझे ऐ आसमाँ/हम अभी से क्यूँ बताएँ क्या हमारे दिल में है। उस दौर का भारत अपने उस दौर के दिल की बात को अब दुनिया भर में और उसे आज भारत महसूस कर रहा है। भारत ने सच में अपने इतने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ यह जो यात्रा दुनिया के टूटते, बिखरते और ध्वस्त होते देशों के साथ पूरी की वह अद्भुत है। उसने अपनी इस यात्रा से बताया कि उसके दिल में क्या था और अभी बहुत कुछ अपने गणराज्य में वह करके विश्व के प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होकर बताने वाला है।

हमारे देश के महान स्वाधीनता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और भारत के निर्माणकर्ताओं को इस पावन अवसर पर हमें स्मरण करना है। उन स्त्रियों को स्मरण करना है जो उन दिनों गाँधी, सुभाष, पटेल, सी। राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू आदि के साथ भारतीय अस्मिता के लिए संघर्ष कीं और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे त्यागी, आत्मबलिदानी व साहसी लोगों के प्राणों के आहुति से प्रेरित होकर देश की स्वाधीनता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लीं। हममें से अधिकांश लोग अज़ीज़न बाई के बारे में नहीं जानते जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बहादुर नायिका थीं। पेशे से नर्तकी-तवायफ होने के बावजूद उन्होंने देशभक्ति में जीवन लगा दिया। उन्होंने 'मस्तानी ढोली' का नेतृत्व किया! लगभग 400 महिलाओं का गुप्त समूह, जो अंग्रेज़ों से जानकारी जुटाता और क्रांतिकारियों तक पहुँचाता। इसके अलावा वे हथियार चलाने और सैनिकों की मदद में भी माहिर थीं। विद्रोह के दौरान उन्हें ब्रिटिशों ने पकड़ लिया। उन्होंने अपने साथियों का राज़ नहीं खोला और शर्तें अस्वीकार की। पेशे से नर्तकी अज़ीज़न बाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ सिपाहियों की अहम जानकारियाँ स्वतंत्रता सेनानियों को देती थी। क्रान्तिकारियों के सहयोग के लिए काम करती थीं। पकड़ी गईं। क्षमा नहीं माँगा। जनरल हैवलॉक ने उन्हें तोप से उड़ा दिया। उनके इस साहस और योगदान के कारण नानासाहेब ने उन्हें बहन समान सम्मान दिया था। उनका साहस आज भी महिलाओं की वीरता और स्वतंत्रता प्रेम की मिसाल है। ऐसी वीरांगनाओं को इस गणतंत्र पर हमें स्मरण करना है।

भारतीय गणतंत्र उन्हें न भूल जिन्होंने कंटकों को कुचलकर इस महान सभ्यता को बचाया है और देश की अस्मिता व पहचान को पुनः स्थापित किया है। भारतीय गणतांत्रिक देश को अपना आकार पाने में इन महान देशभक्तों व बहनों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। आज जब देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है तो भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज वितरण किया जाता है। अनेक सड़कों, पुलों और रेलवे स्टेशन पर खुले आसमान में सोते लोगों को देखकर मन भर जाता है। भीखारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत के राजस्थान जैसे राज्य में बाल विवाह पूर्णतया बंद करने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। धर्म और जाति के भी मामले भारतीय सहिष्णुता को प्रश्नांकित करने लगे हैं। हमारे स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, मानव विकास सूचकांक में अभिवृद्धि ज़रूरी है। हैपीनेस इंडेक्स की बढ़ोतरी के लिए अवरसंरचात्मक विकास, जलवायु न्याय और सामाजिक-सांस्कृतिक सातत्य के लिए मुखर होना पड़ेगा। हमारी दैयनन्दिन की ज़रूरतों को ठीक करना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी की मांग के मुताबिक उनके सपनों के हिसाब का भारत बनाना ज़रूरी होगा लेकिन यह फिक्र तभी कम होगी जब हमारी इच्छाशक्ति, विजन-प्लान व लीडरशिप सशक्त, पारदर्शी व गंभीर पहल करेगी। वास्तव में मुख्यधारा से लेकर हाशिये के समाज तक योजनाओं का पूर्णतया नियोजन व प्रतिभागिता व लाभार्थी बनाने की चेष्ठा होगी। इसी बात का आभाव तो देश को खोखला बना देता है। यदि ऐसी व्यवस्था भारतीय गणराज्य कर सका होता तो देश में कोविड काल में इतनी मौतें न होतीं। हमारे स्वास्थ्य संबंधी अवरसंरचना को ज्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की भी है कि सुदूर स्थित कोई बीमार महिला, गर्भवती महिला या मृत लोगों को समय पर वाहन मिल जाए और उनके बुरे वक़्त में परिजनों को सहायता मिल जाए। इस गणतंत्र हम अपने पड़ोसियों के दुःख-सुख में सहभागी होने की हम शपथ लें। सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए तत्पर हो और वैश्विक स्तर पर ख्याति व उपलब्धियों के शानदार प्रदर्शन के लिए हर भारतीय मन तैयार हो तो देश अपने गणतंत्र की जयघोष खुद करने या प्रचारित करने के लिए नहीं सोचेगा अपितु पूरी दुनिया भारतीय गणतंत्र की जय-जयकार करेगी।

सबसे अच्छी बात यह है कि भारत निराश नहीं है। भारत निरंतर अपने विकास के कीर्तिमान स्थापित भी कर रहा है। स्पेश, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र, डिजिटल क्रांति के लिए भारत को संपूर्ण विश्व में सम्मान प्राप्त है। अब तक की भारतीय संवैधानिक यात्रा दुनिया के अनेक देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्तम मानी जा रही है। इसलिए आज आशावादी देश भारत अपने देश के गणतांत्रिक मूल्यों के साथ हिमालय सा मस्तक ऊंचाकर आगे बढ़ने को तैयार है। देश के नागरिकों को अपने कर्तव्य का वैयक्तिक व सामूहिक स्तर ज्यादा समझने की आवश्यकता है। हम सब कामना करें इस 77 वें गणतंत्र पर भारत गणतंत्र तुम्हारी जय हो! यह देश निर्भय हो। इस भावना के साथ ही हम अपने गणतांत्रिक स्वबोध को भी बचा सकेंगे।

'मंत्रा ऑफ सक्सेस'

राजेश शर्मा
लेखक सीनियर जर्नलिस्ट एवं मोटिवेशनल स्पीकर हैं

त्याग- तपस्या की मूरत बुधरी ताती को मिला पद्मश्री

महिला सशक्तिकरण की मिसाल बुधरी ताती की कहानी जिद जुनून और ज़ज्बे से भरी...

भारत के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण में से एक पद्मश्री से सम्मानित होना सचमुच गौरव के पल हैं। गणतंत्र दिवस-26 पर घोषित पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री से सम्मानित 'बुधरी ताती' आज देश और दुनिया की सुर्खियों में हैं। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बुधरी ताती की कहानी जिद जुनून और ज़ज्बे से भरी है। त्याग- तपस्या की मूरत बुधरी ताती को पद्मश्री से सम्मानित होना मानों यह सम्मान धन्य हो गया। पढ़िए उनकी साहस भरी कहानी।

बुधरी ताती, ये नाम शायद आपने पहले ना सुना हो। लेकिन दक्षिण बस्तर में बुधरी ताती महिला सशक्तिकरण का दूसरा नाम है। दक्षिण बस्तर यानि दंतेवाड़ा से अबूझमाड़ तक फैला धुर नक्सल प्रभावित इलाका। एक ऐसा इलाका जहां चप्पे-चप्पे पर मौत अपना शिकार ढूंढती है। बारूद, गोली, एनकाउंटर, पुलिस-नक्सली संघर्ष वाले इस क्षेत्र में बुधरी ताती 80 के दशक से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता की अलख जगा रही हैं। 1985 में 12 आदिवासी बच्चों के छात्रावास को शुरु कर अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत करने वाली बुधरी ताती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

1986 से 1987 तक पूरे वर्ष भर अबूझमाड़ में पैदलयात्रा कर 400 गांवों से संपर्क साधा और वहां रहने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने का काम बुधरी ताती ने किया है। महज 15 वर्ष की आयु में शुरु हुआ बुधरी ताती का सफर यहीं नहीं रुका, उन्होंने 1990 में 11 बालिकाओं के साथ कन्या छात्रावास भी शुरु किया। बचपन में ही स्कूल छोड़ देने वाली महिलाओं को खोज-खोजकर पढ़ाने वाली बुधरी ताती खुद केवल 10 वीं पास हैं। उनके प्रयास से 550 आदिवासी महिलाओं ने

सिलाई, बुनाई और अन्य हुनर सीखकर कुटीर उद्योग चलाने के लिए ट्रेनिंग ले चुकी हैं। बुधरी ताती ने अबूझमाड़ के कई गावों में लोगों को प्रतिदिन नहाना सिखाया। देवी प्रकोप के डर से दवाई ना खाने वाले आदिवासियों को बुधरी ताती ने दवाई खाना सिखाया। उनके मन का डर दूर किया कि दवाई खाने से देवी-देवता नाराज नहीं होते हैं।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सुदूर बस्तर के हीरानार में बुधरी ताती वृद्धाश्रम भी चला रही हैं। उनकें वृद्धाश्रम में कई बूढ़ी महिलाओं को पनाह मिली हुई है, जिन्हें किसी कारणवश अपना घर नसीब नहीं है। तिस पर हकीकत ये भी कि बुधरी ताती को कोई सरकारी सहायता नही मिली।

केवल उनके वृद्धाश्रम को न्यूनतम सरकारी मदद मिलती है। बच्चों का छात्रावास, आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य का अभियान बुधरी ताती अपने दम-खम से ही चला रही हैं। उनका साथ उनकी परछाई की तरह शांति बेक देती हैं, जो रिश्ते में उनकी भतीजी हैं। बुधरी और उनकी टीम की सभी महिलाओं ने अविवाहित रहने का संकल्प लिया है और अपना पूरा जीवन बस्तर के लोगों के नाम कर दिया है।

- अपना पूरा जीवन बच्चियों, महिलाओं के उत्थान व बुजुर्गों की सेवा में समर्पित कर दिया।
- अब तक उनके प्रयास से 551 महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं।
- 10 महिलाओं के साथ कर रही बड़े काम।
- छत्तीसगढ़ शासन के वीरनी पुरस्कार से अलंकृत।
- पं सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर ने उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया है।
- बुधरी और उनकी टीम की सभी महिलाओं ने अविवाहित रहने का संकल्प लिया है और अपना पूरा जीवन बस्तर के लोगों के नाम कर दिया है।

विद्यावती बड़जात्या का स्वर्गवास हो जाने पर बड़जात्या परिवार द्वारा नेत्रदान किया गया

धार मानव सेवा कल्याण समिति द्वारा धार नगर में किया गया 30वां नेत्रदान

धार। आनंदेश्वर मार्ग निवासी स्वर्गीय बसंतीलाल अनारद वाले की धर्मपत्नी एवं राजेंद्र बड़जात्या की माता जी श्रीमती विद्यावती बड़जात्या (अनारद वाले) का स्वर्गवास हो गया। उनके पुत्र राजेंद्र बड़जात्या ने उनके नेत्रदान का निर्णय लिया। धार मानव सेवा कल्याण समिति के माध्यम से एवं भोज हॉस्पिटल के नेत्र विभाग के डॉ. सौरभ बौरासी एवं उनकी सहायक प्रियंका साधु व पिंकी के सहयोग से नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण की। ये बड़जात्या (जैन) परिवार द्वारा किया गया तीसरा एवं एक सप्ताह में किया गया दूसरा नेत्रदान है ।

धार मानव सेवा कल्याण समिति द्वारा धार नगर में किया गया 30 वां नेत्रदान है। धार मानव सेवा कल्याण समिति द्वारा उनकी माताजी के नेत्रदान करने हेतु उठावना अवसर पर समस्त बड़जात्या परिवार को अभिनंदन पत्र और स्मृति-चिन्ह प्रदान कर सम्मानित कर आभार व्यक्त किया गया ।

मानतुंगगिरी तीर्थ क्षेत्र पर चंद्रमति माताजी के सानिध्य में मनाया गणतंत्र दिवस

धार। दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र मानतुंगगिरी धार पर गणतंत्र दिवस तीर्थ क्षेत्र प्रेरक क्षुल्लिका चन्द्रमति माताजी के पावन सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर जैन समाज के साथ साथ भारत विकास परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम मंगलाचरण रेखा कासलीवाल द्वारा किया गया। अतिथि स्वागत मौसम झांझरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर अशोक कासलीवाल, वीरेंद्र बड़जात्या, ममता गंगवाल, नीता झांझरी, मुरलीधर बूटे, श्री टोंग्या , प्रकाश गुप्ता, आदि ने गणतंत्र दिवस पर अपने विचार रखते हुए शुभकामनाएं दी। क्षुल्लिका चंद्रमती माताजी ने आशीर्वाद देते हुए गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन किशोर जैन तथा आभार संजय गंगवाल द्वारा किया गया। तत्पश्चात राष्ट्र ध्वज और जैन धर्म ध्वजा फहराई। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सदस्यों द्वारा क्षेत्र पर पौधारोपण भी किया गया। जानकारी मीडिया प्रभारी संजय गंगवाल ने दी।

गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह नेहरू महाविद्यालय में सम्पन्न हुआ

सोहागपुर। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय परिसर में संम्पन्न हुआ। समारोह जनपद पंचायत अध्यक्ष जालमसिंह के मुख्य आतिथ्य एवं नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल का अध्यक्षता में हुआ।इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी, एसडीओ पुलिस संजू चौहान,नगर निरीक्षक उषा मरावी के अलावा प्रशासनिक अधिकारी, राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक, विभिन्न शालाओं के छात्र छात्राएं, शिक्षक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मुख्य समारोह में विभिन्न शालाओं के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अतिथियों ने पुरस्कारों का विवरण किया। इधर राजनीतिक दलों ने अलग-अलग स्थानों पर झंडा फहराया।

प्रदेश की प्राचीन धरोहर कमानिया गेट पर कई वर्षों बाद रंग-रोगन, विद्युत की रोशनी हुई

सुबह सवेरे सोहागपुर। प्रदेश में दो धरोहर एक कमानिया जबलपुर, दूसरा प्राचीन कमानिया गेट सोहागपुर में स्थित है। विगत वर्षों से नगर पंचायत परिषद इसके रखरखाव के प्रति उदासीन हो गई थी। मरम्मत को तो छोड़ दें। रंग रोगन से भी इस धरोहर को वंचित कर दिया गया था। इसके पूर्व 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को रंग रोगन के अलावा कमानिया गेट को विद्युत की रोशनी से जगमगाया जाता था। लेकिन इस साल कुछ नया हो रहा है। 26 जनवरी के पूर्व कमानिया गेट की मरम्मत की गई। वहीं अब उत्कृष्ट रंग रोगन किया जा रहा है। रंग रोगन में उभरें आकार में मयूर पर कलर किया जा चुका है।शेष उभरी किनारियों पर भी कलर किया जाना है। लेकिन मयूर उत्कृष्ट आकृति को देखकर नागरिक ठिठककर देखते रहे। वहीं कई नागरिक, महिलाएं मयूर की सेल्फी लेते देखे गए।

इस कार्य के लिए नगर पंचायत परिषद अध्यक्ष, पार्षदों सहित नगरपालिका अधिकारी का हृदय सेआभार व्यक्त किया जा रहा है। उक्त कमानिया गेट राजेन्द्र वार्ड में आता है।

इसके लिए राजेन्द्र वार्ड पार्षद गौरव पालीवाल को धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं।

यदि कमानिया गेट के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इसका निर्माण प्रेम क्लब ने तत्वावधान में कराया गया था। प्रेम क्लब में स्वर्गीय गोपालचंद खंडेलवाल उनको सभी गोपाल काकाजी, गोपाल सेठ के नाम से प्रसिद्ध थे। दूसरा अहम नाम आता है स्वर्गीय द्वारकाप्रसाद मिश्रा, तीसरा नाम स्वर्गीय मुक्दीलाल मालवीय, चौथा नाम स्वर्गीय लक्ष्मणदास गोलानी जो लक्ष्मन सेठ के नाम विख्यात थे। उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद नरसिंहपुर के प्रथम सांसद हरि विष्णु कामथ के साथ क्षेत्र में चुनावी बागडोर उनके हाथों में रहती थी। वहीं सोहागपुर में एक या दो दिन के प्रवास के समय विश्राम गृह में न रहकर उनके निवास स्थान सिन्धी कालोनी शास्त्री में रहते थे। स्वर्गीय गोलानी क्षेत्र में भाजपा के पहले झंडाबरदार संस्थापक सद्स्यों में से थे। उस समय जब कोई भी व्यक्ति भाजपा का झंडे लगाने से डरते थे। उस समय वो भाजपा का झंडा थामे रहते थे। क्षेत्र में भाजपा एक छोटा सा वृक्ष लगाया था।आज उस वट वृक्ष की छाया कौन कौन ले रहा है ।

पांचवां नाम स्वर्गीय गुलाबचंद खंडेलवाल का आता है। ये सभी प्रेम क्लब के साथी थे। उल्लेखनीय है कि श्री खंडेलवाल के पिता स्वर्गीय मूलचंद खंडेलवाल ने सोहागपुर में पहले गणपति की स्थापना की थीं। तभी से सोहागपुर में क्रमशः गणपति स्थापना होती रही हैं।

बाद में स्वर्गीय गुलाबचंद खंडेलवाल ने स्टेशन रोड पर गणेश मंदिर की स्थापना की थीं। बाद उनके पुत्र अभय खंडेलवाल ने मंदिर को उत्कृष्ट आकृति प्रदान की है।इसके अलावा भी प्रेम क्लब एवं कमानिया गेट निर्माण में करीबन अन्य दो या तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति भी साथ थे। लेकिन उनकी जानकारी इस प्रतिनिधि को मिल नहीं पा रही है।

शासकीय माध्यमिक विद्यालय महाकाल कॉलोनी पुरस्कृत

देवास। गणतंत्र दिवस पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय महाकाल कॉलोनी को पुरस्कृत किया गया। प्रधानाध्यापक महेश सोनी ने बताया कि विद्यालय को आईएसओ अवार्ड मिलने पर पुलिस परेड ग्राउंड पर जिलाधीश ऋतुराज सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत, नगर निगम आयुक्त दलीप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष लीला अटारिया द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई झांकी में भी विद्यालय की सहभागिता रही। बीआरसी किशोर वर्मा ने बताया, कि शासकीय माध्यमिक स्तर के विद्यालय में आइएसओ अवार्ड प्राप्त करने वाला महाकाल कॉलोनी स्कूल मध्यप्रदेश में प्रथम है। विद्यालय द्वारा सभी क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर बीआरसी वर्मा, राजेश चौहान, नाजमा खान, शकुंतला मालवीय अलका परमार, प्रियंका गौड़, सूर्यबाला बघेल एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

इंदौर में यूथ कांग्रेस की जन अधिकार यात्रा आज से

दूषित पानी के विरोध में होगा आयोजन, मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ देने की मांग

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंदौर जल त्रासदी को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष अमित खत्री, रवि परमार और अभिज्ञान शुक्ला मौजूद रहे।

यश घनघोरिया ने कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई मौतें हत्या के समान हैं। भाजपा की नाकारा और असंवेदनशील सरकार इस पूरे मामले में सच्चाई छुपाने का प्रयास कर रही है। सरकार के आंकड़े वास्तविकता को नहीं दर्शाते, जबकि अब भी हजारों लोग प्रभावित हैं और 200 से 250 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं।

उन्होंने बताया कि 2 जनवरी को यूथ कांग्रेस ने इंदौर नगर निगम का घेराव किया था, लेकिन सरकार और प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाल ही में महू में भी इसी तरह की घटना दोहराई गई, जहां दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हुए और एक व्यक्ति की मौत हो गई।

मंत्रियों की भाषा पर सवाल- यश घनघोरिया ने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंत्री और महापौर ने

पीड़ितों को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसे बयान जनता की भावनाओं का अपमान हैं और लोकतंत्र में यह स्वीकार्य नहीं है।

28 से 5 तक जन अधिकार न्याय पदयात्रा- युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया कि 28 जनवरी से 5 फरवरी तक प्रदेशव्यापी 'जन अधिकार न्याय पदयात्रा' निकाली जाएगी। पदयात्रा की शुरुआत इंदौर की 9 विधानसभा क्षेत्रों से होगी और माता अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष की प्रेरणा माता अहिल्या से मिलती है। इस पदयात्रा में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेतृत्व भी शामिल होगा।

विंध्य पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति के रंग में रंगा

देवास। विंध्य पब्लिक स्कूल, शिव शक्ति नगर, देवास में गणतंत्र दिवस समारोह अत्यंत गरिमामय एवं देशभक्ति से ओतप्रोत वातावरण में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं भारत माता के पूजन, दीप प्रज्वलन एवं ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र को सलामी देकर किया गया।

कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार- मोहन वर्मा अध्यक्ष, एक्ट इंव फाउंडेशन एवं सहज सरकार जन शिक्षक उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के संचालक तरुण मिश्रा एवं प्रधानाध्यापिका सुश्री संतोष सिसोदिया द्वारा हार एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। स्वागत उपरांत विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के मार्गदर्शक श्री अरुण मिश्रा ने स्वागत भाषण देकर सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों, लोकनृत्यों एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को जीवंत बना दिया। विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों ने नृत्य, समूहगान एवं नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से देशप्रेम, एकता एवं सामाजिक मूल्यों का प्रभावशाली संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताओं, विज्ञान प्रदर्शनी एवं कक्षा-स्तरीय गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिससे विद्यार्थियों में उत्साह का संचार हुआ।

विशेष अतिथि मोहन वर्मा ने अपने उद्बोधन में जल संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देते हुए विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी।

वहीं मुख्य अतिथि सहज सरकार ने विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के उत्कृष्ट परिणामों के लिए बधाई देते हुए विद्यालय प्रबंधन को इस सफल आयोजन हेतु साधुवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती दिव्या पांचाल एवं श्रीमती रोशनी वर्मा द्वारा किया गया। अंत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा सभी अतिथियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। यह समारोह विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक एवं स्मरणीय सिद्ध हुआ।

प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया

देवास। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (PIMR), देवास में 77वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ, जिसके पश्चात राष्ट्रगान का गायन किया गया। इस अवसर पर प्रेस्टीज एजुकेशन फ़ाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. डेविश जैन ने वर्चुअल माध्यम से गणतंत्र दिवस का संदेश दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान के मूल्यों को अपनाने, अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करने तथा राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात संस्थान की डायरेक्टर प्रो. डॉ. आशिमा जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र दिवस हमें केवल हमारे अधिकारों की ही नहीं, बल्कि कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगों का महत्व बताते हुए कहा कि केसरिया रंग साहस, श्वेत रंग शांति तथा हरा रंग विकास का प्रतीक है।

गणतंत्र दिवस पर दत्ताजी उन्नगावकर स्मृति न्यास सृजन कार्यालय पर गरिमामय समारोह में हुआ ध्वजारोहण

धार। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर श्री दत्ताजी उन्नगावकर स्मृति न्यास, धार द्वारा त्रिमूर्ति स्थित सृजन कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण एवं झंडा वंदन कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर नगर संघ चालक डॉ. दिनेश कर्मा द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थितजनों ने राष्ट्रध्वज को नमन कर गणतंत्र के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविद अभय किरकिरे विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में दैनिक जीवन में 'पंच परिवर्तन' के प्रभाव तथा समाज संगठन की अवधारणा पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब

समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण, विचार, स्वच्छता, समरसता एवं सामाजिक दायित्वों में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, तभी एक सशक्त, संगठित और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण संभव है।

कार्यक्रम में संघ पदाधिकारी, सदस्यगण एवं नगर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। उपस्थितजनों ने भारतीय संविधान के मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सामाजिक समरसता को बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। कार्यक्रम में न्यास के उपाध्यक्ष महेश अग्रवाल, सचिव वैभव कुमार मोदी एवं कोषाध्यक्ष शिरीष मुकादम उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिप्रा के तट पर उज्जैन में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, ली परेड की सलामी

आकर्षक झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोह लिया दर्शकों का दिल

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत और सिंहस्थ पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों, समारोह में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभागीय झांकियों को पुरस्कृत भी किया। समारोह में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद श्री बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, विभिन्न धर्मो के धर्मगुरू, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

तीन रंग के गुब्बारे छोड़ कर दिया राष्ट्रभक्ति और जनसेवा का संदेश- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्तिक मेला मैदान स्थित शिप्रा तट सुनहरी घाट पर तिरंगा कलर के गुब्बारे खुले आकाश में छोड़ कर राष्ट्रभक्ति और जनसेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर मां शिप्रा में 40 से अधिक तिरंगे रंग से सरावोर नाव पर तिरंगा ध्वज लिए होमगार्ड, एसडीईआरएफ के जवान उपस्थित होकर देश भक्ति के गीत गा रहे थे। घाट पर तिरंगे की थीम पर साज-सज्जा की गई साथ ही घाट पर जनजातीय भील कलाकारों द्वारा भगोरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज राष्ट्र के जन-गण-मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व-गुण के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत माता की आज़ादी के लिए हँसते-हँसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में होना है। इस भव्य-दिव्य आयोजन के उपलक्ष में ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पावन शिप्रा के किनारे आयोजित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया है। मध्यप्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। ज्ञान के मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने 4 मिशन, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती किसानी करने वाले भाईयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2002-03 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 27 हजार 50 करोड़ से अधिक किया गया। समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ाकर 505 करोड़ किया गया है। प्रदेश में लगभग 3 हजार गौशालाएँ पौने पाँच लाख गौमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रहीं हैं।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से 2 हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन

किया गया। किसानों को 1 हजार 360 करोड़ रुपये की बोनस राशि का भुगतान किया गया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावान्तर योजना का लाभ दिलवाया गया। सात लाख से अधिक किसानों को करीब 1300 करोड़ रुपये की भावांतर राशि का भुगतान किया गया है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महत्वपूर्ण रही मध्यप्रदेश की भागीदारी- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जन विश्वास अधिनियम 2024 एवं 2025 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों के विकास को नई दिशा मिली है। प्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग और रोज़गार वर्ष के रूप में मनाया गया।

प्रदेश में नशे के विरूद्ध चलाया जा रहा है जन-जागरूकता अभियान- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए अपराधिक तत्वों पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पहले नक्सल उन्मूलन का कार्य किया गया है। प्रदेश में नशे के विरूद्ध जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

जापान सहित अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से हो रहे हैं स्थापित- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गत वर्ष 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। इनमें से 4 लाख से अधिक आवास बनकर तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना के माध्यम से 20 हजार से अधिक बसाहटों तक सड़क की सुविधा ले जाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस कार्य के लिए 21 हजार करोड़ से अधिक राशि की मंजूरी दी गई है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण का कार्य निरंतर चल रहा है।

प्रदेश के 30 लाख विद्युत पम्प को सोलर पंप में परिवर्तित कराने का लक्ष्य- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो गया है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं को लगभग 10 घंटे प्रतिदिन विद्युत प्रदाय की जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 9 हजार 508 मेगावाट हो चुकी है। मुरैना में प्रदेश की पहली ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू हो रही है जिसकी विश्व बैंक ने भी प्रशंसा की है। प्रदेश में 30 लाख विद्युत पम्प को सोलर पंप में परिवर्तित कराने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर घर नल से जल के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22 हजार से अधिक ग्रामों में सभी घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जबलपुर, देवास और इंदौर को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया।

प्रदेश की तकनीकी संस्थानों में आरंभ होगी कोडिंग लैब

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शिक्षा-दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में गहरी हैं। यह मध्यप्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। स्कूलों में शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाएँ, इसके प्रयास किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 6 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गई है। निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे साढ़े 8 लाख बच्चों की फीस सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए गए। मध्यप्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के साथ ही उसे लाभप्रद, कौशल आधारित एवं रोजगारपरक बनाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में 51 हजार 469 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 55 हजार 633 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो तुलनात्मक रूप से 8 प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजकीय कोष में और अधिक वृद्धि के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास जारी हैं। प्रदेश में विकास गतिविधियों और जनकल्याण के कार्यों के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित मध्यप्रदेश@2047 दृष्टि पत्र का विमोचन किया गया, जो प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'विकसित भारत@2047' संकल्प के अनुरूप प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दिशा तय करेगा।

वन एवं वन्य जीव संवर्द्धन में प्रदेश की विशेष पहचान बनी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन एवं वन्य जीव के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और प्रदेश की विशेष पहचान बनी है। शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सागर जिले में डॉ. भीमराव अभयारण्य और श्योपुर जिले में जहानगढ़ अभयारण्य का गठन किया गया है।

पचमढ़ी अभ्यारण्य से अलग होगा पचमढ़ी नगर

मोहन कैबिनेट देगी मंजूरी, टाइगर रिजर्व में विकास कार्यों के प्रस्ताव भी होंगे मंजूर

भोपाल (नप्र)। पचमढ़ी नगर को पचमढ़ी अभ्यारण्य से अलग किए जाने को लेकर एक बार फिर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। जिसे आज मोहन सरकार मंजूरी देगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पहले भी कैबिनेट फैसला कर चुकी है, लेकिन प्रस्ताव में तकनीकी गलती के चलते पचमढ़ी नगर को अभ्यारण्य से बाहर नहीं किया जा सका था।

इसलिए अब दोबारा प्रस्ताव लाकर पचमढ़ी अभ्यारण्य और पचमढ़ी नगर की सीमा अलग-अलग रखने को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व एरिया में बफर जोन में विकास कार्यों के प्रस्ताव भी मंजूर किए जाएंगे।

गणतंत्र दिवस के बाद हो रही इस पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट के साथियों के साथ दावोस यात्रा के अनुभव साझा करने के साथ वहां मिले निवेश प्रस्तावों की जानकारी भी देंगे। इसके अलावा सरकार की आगामी प्राथमिकताओं पर भी चर्चा

होगी।

इन प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी- मोहन कैबिनेट की बैठक में आज पचमढ़ी अभ्यारण्य की सीमा में पचमढ़ी नगर की नजूल भूमि को अभ्यारण्य की सीमा से अलग किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।

वन विभाग के प्रस्ताव पर टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बफर जोन के विकास को भी मंजूरी मिलेगी। जल संसाधन विभाग के प्रस्ताव पर तवा परियोजना दायीं तट नहर की बागरा शाखा नहर होज सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिलेगी।

तवा परियोजना की दायीं तट नहर से पिपरिया ब्रांच केनाल होज सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी जाएगी।

जनजातीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर 15 परियोजनाएं आगामी वर्षों में चालू रखने को भी मंजूरी मिलेगी।

सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के लिए वर्तमान कार्यक्रम चालू रखने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को भी कैबिनेट मंजूर करेगी।

पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2022 के नाम व मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किए जाने के प्रपोजल को भी मंजूरी मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में सिवनी जिले के सिमरिया गांव में मौजूद खसरा नम्बर 90 की रकबा 0.60 हेक्टेयर भूमि पर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का गोदाम बन जाने पर भूमि स्वामी को मुआवजा दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में महाकाल मंदिर की वीआईपी दर्शन याचिका खारिज

हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा ; गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा कलेक्टर ही तय करेंगे

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नेताओं और वीआईपी को प्रवेश देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे पहले इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही इंदौर हाईकोर्ट का फैसला महाकाल मंदिर समिति पर लागू रहेगा, जिसमें उज्जैन कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे तय करें कि कौन वीआईपी है और कौन नहीं।

दरअसल, महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद इंदौर के अधिवक्ता चर्चित शास्त्री और दर्पण अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि देशभर से लाखों श्रद्धालु महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, जबकि नेता और प्रभावशाली लोग आसानी से गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा।

गर्भगृह में प्रवेश का फैसला फिलहाल कलेक्टर करेंगे- करीब छह महीने पहले इंदौर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया था कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, यह तय करने का अधिकार उज्जैन कलेक्टर के पास है। अदालत ने कहा कि यदि कलेक्टर किसी विशेष दिन किसी व्यक्ति को अनुमति देते हैं, तो उसे वीआईपी माना जाएगा।

ढाई साल से बंद है गर्भगृह- दरअसल, 4 जुलाई 2023 को सावन महीने में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर का गर्भगृह 11 सितंबर 2023 तक बंद कर दिया गया था। उस समय मंदिर समिति ने कहा था कि सावन माह के समाप्त होते ही गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद गर्भगृह खुला नहीं है। महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में रोजाना 20 से 30 हजार श्रद्धालु आते थे।

मित्तल हॉस्पिटल की नवीन ईकाई विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ 28 जनवरी को

धार। धार शहर और जिले के प्रसिद्ध मित्तल हॉस्पिटल द्वारा धार शहर एवं जिलेवासियों को बेहतर और अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक और सौगात दी जा रही है। मित्तल हॉस्पिटल की नवीन ईकाई के रूप में धार शहर में विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ 28 जनवरी को किया जा रहा है।

भव्य और गरिमामय समारोह में विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ होने जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा, विशेष अतिथि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, धार की यशस्वी विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री निलेश भारती रहेंगे। मित्तल हॉस्पिटल के संचालक डॉ.उमेश मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि एसपीडीए ग्राउंड के सामने मगजपुरा रोड पर यह भव्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मॉडर्न चिकित्सा और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेंगा। जिस तरह से मित्तल हॉस्पिटल ने धार शहर और जिले में अपनी पहचान और विश्वसनीयता कायम की हैं उसी तरह विनायक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी आप सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा।

शंकराचार्य से सबूत मांगना प्रशासनिक मर्यादा का उल्लंघन

उमा भारती ने अविमुक्तेश्वरानंद को यूपी सरकार के नोटिस पर बोला हमला, कहा-सकारात्मक समाधान निकलेगा

भोपाल (नप्र)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2026 के माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच जारी विवाद अब राजनीतिक और धार्मिक दोनों मोर्चों पर गरमा गया है।

इस विवाद में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी सामने आ गई हैं और उन्होंने एक ट्वीट के जरिए योगी सरकार तथा प्रशासन की कड़ी आलोचना की है।

पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच तनातनी चल रही है। प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से 'शंकराचार्य' होने का कोई प्रमाण/सबूत प्रस्तुत करने को कहा था, जिसे लेकर विवाद और गहरा गया। प्रशासन का कहना है कि मेले के प्राधिकरण ने यह नोटिस इसलिए जारी किया क्योंकि शीर्ष अदालत के आदेश के मुताबिक किसी को 'शंकराचार्य' की उपाधि का उपयोग करने की अनुमति नहीं है जब तक कि विवादित अपील पर फैसला नहीं हो जाता।

उमा भारती का ट्वीट- पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया (एक्स) पोस्ट में लिखा कि उन्हें विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज और उत्तर प्रदेश

सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से शंकराचार्य होने के सबूत मांगकर प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं और अधिकारों का उल्लंघन किया है। उनके अनुसार यह अधिकार केवल शंकराचार्यों तथा विद्वत परिषद को ही होना चाहिए, न कि सरकार या प्रशासन को।

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या प्रशासन धर्म और धार्मिक परंपराओं को समझते हुए इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अपने ट्वीट में टैग करते हुए सीधा संदेश दिया कि इस मामले में संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखना जरूरी है।

सबसे पहले उमा भारती ने ट्वीट में कहा मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है, यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों का एवं विद्वत परिषद का है।

यह विवाद 17 जनवरी को माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन शुरू हुआ था, जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद संगम घाट पर स्नान के लिए पहुंचे थे। प्रशासन ने उनके रथ/पालकी आदि को लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए, जिससे दोनों पक्षों में कथित झड़प हुई तथा विवाद बढ़ गया।

इसके बाद प्रशासन ने उन्हें 'शंकराचार्य' उपाधि के इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में स्वामी ने यह दावा किया कि उन्हें अन्य शंकराचार्यों द्वारा भी मान्यता दी गई है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस के जवाब में कहा कि शंकराचार्य वह होता है जिसे अन्य तीन प्रतिष्ठित शंकराचार्य मान्यता देते हैं और उनके अनुसार उन्हें द्वारका तथा श्रृंगेरी के शंकराचार्यों द्वारा भी सम्मान दिया गया है।

अविमुक्तेश्वरानंद पर बीजेपी में भी मतभेद

उमा भारती के बयान के बाद यह विवाद राजनीतिक रूप से भी उभर रहा है। भाजपा के भीतर भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं, जहां कुछ नेता प्रशासन के पक्ष में हैं तो कुछ धर्म-संस्कृति के दृष्टिकोण से अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हैं। विपक्षी दल भी भाजपा की सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि धार्मिक मामलों को लेकर संवेदनहीनता दिखाई जा रही है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक पिछले कई दिनों से धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उन्हें सम्मानपूर्वक संगम स्नान का अधिकार दिया जाए। इस बीच कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के इस्तीफे और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

राइट क्लिक

सनातनी एकता पर गहरी चोट है यूपी का यह 'सवर्ण संघर्ष'...

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

उत्तर प्रदेश में दो सनातनियों के बीच छिड़ी जंग अब खुलकर जिस तरह ब्राह्मण बनाम ठाकुर में तब्दील हो गई है, उससे सबसे ज्यादा खुशी शायद डीएमके जैसी पार्टियों को होगी, जिन्होंने दो साल पहले सनातन पर हमला बोलते हुए इसे मलेरिया और डेंगू जैसा रोग बताया था। इसके जवाब में भाजपा और आरएसएस ने सनातन के मुद्दे पर सभी हिंदुओं को एक करने का अभियान चलाया था, जिसकी अब यूपी में खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। यहां लड़ाई धर्मसत्ता बनाम राजसत्ता के साथ-साथ मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिषपीठ शंकराचार्य के बीच हो रही है। योगी जाति से ठाकुर हैं तो शंकराचार्य ब्राह्मण हैं। मौनी अमावस्या पर माघ मेले में मेला प्रशासन द्वारा शंकराचार्य के अपमान से आहत होकर पहले एक ब्राह्मण अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दिया तो जवाब में अयोध्या के जीएएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने (ठाकुर) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ब्राह्मण शंकराचार्य द्वारा अपमान से दुखी होकर पद से त्यागपत्र दे दिया। अगर यह दुर्भाग्यपूर्ण विवाद यहीं नहीं थमा तो इसकी चिंगारियां यूपी में दूर तक फूटेंगीं। लग नहीं रहा कि कोई इस विवाद को खत्म करने में दिलचस्पी ले रहा है, बल्कि इसकी आड़ में अलग चालें चली जा रही हैं। सवाल यह है कि इस योगी बनाम शंकराचार्य प्रकरण में असली टारगेट कौन है? क्योंकि योगी खुलकर शंकराचार्य पर हमला कर उन्हें कालनेमि (असुर) और नियम कायदों का उल्लंघन करने वाला बता चुके हैं तो पिछड़ी जाति से आने वाले राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य से उनके अपमान के लिए माफी मांग चुके हैं। उधर शंकराचार्य हैं कि अपनी बात पर अड़े हैं और उन्होंने सरकारी पद छोड़ने वाले अलंकार को ब्राह्मणों में अकेला 'अलंकार' बताकर उनकी तारीफ की है। अग्निहोत्री ने भी अपने इस्तीफे के साथ राज्य में 56 ब्राह्मण विधायकों के जमीर को चैलेंज किया है कि वो अपमान सहकर भी चुप क्यों हैं तो दूसरी तरफ प्रशांत कुमार सिंह इस बात से व्यथित है कि धर्माधीश शंकराचार्य संवैधानिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री को अपमानित कर रहे हैं।

यह अपने आप में अभूतपूर्व एवं अप्रिय स्थिति है और हिंदू एकता के तमाम दावों तथा आंतरिक मतभेद तथा जातिभेद भुलाने की कोशिशों पर पानी फेरने जैसी है। सवाल तो यह उठ रहा है कि अगर सवर्ण भी एक नहीं हो पा रहे हैं तो बाकी हिंदू जातियों का क्या? इसी तरह सनातन का व्यावहारिक अर्थ सत्ता और स्वार्थ के लिए सनातन संघर्ष ही है तो इस सनातन का व्यापक हिंदू एकता के लिए क्या मायने हैं?

बड़ा सवाल यह भी है कि एक छोटी घटना ने इतना व्यापक और गंभीर रूप कैसे ले लिया कि उनकी गूंज धर्म और राजनीति के साथ-साथ समूचे प्रशासन में भी होने लगी। एक शीर्ष हिंदू संत के अपमान का मुद्दा सवर्ण जातियों में ही ऊर्ध्व विभाजन का कारण कैसे बन गया? अगर वर्णाश्रम व्यवस्था की दो शीर्ष जातियां ब्राह्मण और क्षत्रिय भी एक नहीं हो सकते तो फिर बाकी जातियों को एक जाजम पर लाने के दावों में कितना दम है।

यूपी में यह लड़ाई ब्राह्मणों के आत्मसम्मान की रक्षा और ठाकुरों के वर्चस्व की ही है अथवा इसके पीछे कोई और चाल है, यह अभी स्पष्ट होना है। यह सही है कि देश में ब्राम्हणों की सर्वाधिक यानी करीब 12 फीसदी यूपी में ही है। इस मायने में ब्राह्मणों का समर्थन या विरोध सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता आया है। 2007 में ब्राह्मण बसपा के साथ गए तो मायावती की सरकार बनी तो 2012 में ब्राह्मणों के बड़े वर्ग का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ तो सपा की सरकार बनी। 2014 में केन्द्र में मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद यूपी में ब्राह्मण फिर भाजपा के साथ हुए और आज भी बड़ा तबका भाजपा के साथ ही है। लेकिन शंकराचार्य बनाम योगी प्रकरण से ब्राह्मणों के भगवा जुड़ाव पर भी प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। इस लड़ाई में विपक्ष ब्राह्मणों के साथ है जबकि भाजपा ब्राह्मणों की इस बगावत से शायद यह सोचकर बेफिकर है कि ब्राह्मण भाजपा को छोड़कर कहां जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण तो खुद सनातन की धुरी है। लेकिन यह 'टेकन फॉर ग्रांटेड' वाली स्थिति है। जबकि ब्राह्मणों का मानना है कि योगी राज में उनकी हर स्तर पर न केवल उपेक्षा हो रही है, बल्कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है। शंकराचार्य प्रकरण इसका उदाहरण है। उनका यह भी मानना है कि ब्राह्मणों का श्राप जिसे लगा, वो ठिकाने लग गया। जबकि ठाकुरों का मानना है कि अब वक्त बदल चुका है। योगी आदित्यनाथ निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और सरकार को हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर ही चला रहे हैं। उनका विरोध संवैधानिक सत्ता का विरोध है, जो किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता।

हालांकि शंकराचार्य को लेकर संत समाज भी दो भागों में बंटा है। भाजपा समर्थक संतों का कहना है कि प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य को संगम स्नान के लिए रथ पर सवार होकर जाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि नियम सभी के लिए बराबर है। जबकि शंकराचार्य का कहना है कि उन्हें प्रशासन ने केवल संगम पर जाने से रोका बल्कि उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर शंकराचार्य के रूप में वैधता का प्रमाण पत्र मांगा। इसके खिलाफ वो धरने पर बैठे हैं। यही नहीं, प्रशासन ने दूसरे नोटिस में यह चेतावनी भी दी कि अगर शंकराचार्य ने विरोध खत्म नहीं किया तो क्यों न उन्हें माघ मेले में बैन कर दिया जाए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शंकराचार्य का अपमान जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और सरकार को चुनौती दे रहे हैं। वैसे भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सुर भाजपा और संघ विरोधी ही रहा है। उन्हें जो नोटिस दिया गया, उसका आधार उनकी शंकराचार्य पद पर नियुक्ति की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला है। हालांकि शंकराचार्य का दावा है कि कोर्ट ने उनकी नियुक्ति पर कोई रोक नहीं लगाई है। जैसे-जैसे यह मामला आगे बढ़ रहा है कि भाजपा के असंतुष्ट खेमे से भी शंकराचार्य को समर्थन मिल रहा है। लेकिन भाजपा आला कमान का इस मामले में रवैया अभी भी अस्पष्ट है। इस 'तटस्थता' के दो मायने निकलते हैं या तो यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी की जा रही है या फिर एक तीर से दो निशाने (योगी और शंकराचार्य) साधे जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के प्रति इतनी सहानुभूति नहीं दिखाते। दूसरा, इस बहाने (भाजपा विरोधी) शंकराचार्य को उनकी हैसियत बताने की कोशिश की जा रही है। और इसीके चलते राज्य में ब्राह्मणों की नाराजी की भी चिंता नहीं की जा रही है। एक तर्क यह भी है कि भाजपा इस बार विस चुनाव में 'ब्राह्मण बनाम ऑल' जातीय ध्रुवीकरण कराकर भी चुनाव जीत सकती है। इसमें यह संदेश भी निहित है कि सनातन की ध्वजा अब पहले की तरह ब्राह्मणों के हाथ में नहीं रही। वह गैर ब्राह्मणों के हाथ में जा चुकी है और ब्राह्मण विरोध के मुद्दे पर ज्यादातर अन्य जातियां भाजपा के साथ हैं। वैसे ब्राह्मणों में भी कितने शंकराचार्य के समर्थन में हैं, यह दावे से नहीं कहा जा सकता। दूसरे, योगी को यूपी से हटाना इतना आसान नहीं है। शीर्ष स्तर ऐसी परोक्ष कोशिश पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी हुई थी, जिसका असर चुनाव नतीजों में साफ दिखा। अगर भाजपा योगी को सीएम पद से हटाती है तो उससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि दूसरी तरफ ब्राह्मणों के छिटकने से भी नुकसान होगा। यानी इधर कुआं, उधर खाई वाली स्थिति है। इसके अलावा जिस ब्राह्मण अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने जिन कारणों से पद से इस्तीफा दिया, उनमें एक महत्वपूर्ण कारण जातीय उत्पीड़न के मामले में यूजीसी के बदले नियम हैं। अग्निहोत्री का कहना है कि इस नियम में सवर्णों को स्वतः अपराधी मान लिया गया है। उन्हें जातीय उत्पीड़न के मामले में कोई भी फंसा सकता है। यह अन्याय है। हालांकि इस बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का स्पष्टीकरण आया है कि कोई भी इस कानून का दुरूपयोग नहीं कर सकता। जो भी व्यवस्था होगी वह संविधान की परिधि में होगी। यह व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गई है। उनके मुताबिक यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य कैंपस पर जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह समाप्त करना है। इन नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों) में इक्विटी कमेटी गठित करने का प्रावधान है, जो शिकायतों की जांच करेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई (जैसे डिग्री रोकना, संस्थान की मान्यता रद्द करना आदि) कर सकेगी। यूजीसी ने 13 जनवरी को इन नियमों को अधिसूचित किया था। देश में इस नियम का व्यापक विरोध शुरू हो गया है। विरोधियों का कहना है कि नए दिशा- निर्देशों में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार केवल कुछ वर्गों तक सीमित कर दिया गया है, जहां केवल अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग ही शिकायत कर सकते हैं, जो अपने आप में पक्षपातपूर्ण है। नए एक्ट में झूठी शिकायतों पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है, जिससे दुरुपयोग का खतरा है।

समग्रता में देखें तो पहले राजसत्ता धर्मसत्ता से वैधता चाहती थी तो अब धर्मसत्ता राजसत्ता से वैधता मांग रही है। हालांकि बहुत से सनातनियों का मानना है कि भले ही शंकराचार्य अपनी सत्ता के लिए अदालतों में मुकदमें लड़ रहे हों, लेकिन जनमानस में उनके प्रति आदर और सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो धर्माधीश हैं। लेकिन आज धर्मसत्ता के लिए शंकराचार्यों का यह आचरण आदि शंकराचार्य के उस मूल सिद्धांत 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्यू' के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। यहां सारी लड़ाई धर्म को सत्ता मानकर उस पर काबिज रहने तथा गृहस्थाश्रम को छोड़ दें तो बाकी तमाम सांसारिक सुखों को उपभोगने की है।

इसमें दो राय नहीं कि आज भारत में जितने भी खुद को संत महात्मा पीठाधीश्वर आदि कहलवाने वाले लोग हैं, वो धर्म के प्रचारक भले हों, धर्म के नियंता और रक्षक तो शायद ही हैं। 'संत को कहा सीकरी सों काम' की निर्मोही लेकिन नैतिक सत्ता वाले संत अब दुर्लभ हैं। कथावाचकों, बाबाओं, धर्माधिकारियों और धर्म के नाम पर स्वघोषित धर्माचार्यों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसी तादाद में इनके भक्तों की तादाद भी बढ़ रही है। कौन कब किस बाबा का चोला पहन कर अवतरित हो जाए और लोग अपने विवेक को ताक पर रखकर उसकी सेवा में लीन हो जाए, कहा नहीं जा सकता। धर्म और धर्माचार्यों की महत्ता का आदर होना ही चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में पाखंड और सांसारिक सुखों के लिए निम्न स्तर की लड़ाई का विरोध भी जरूरी है। वरना एक आम इंसान और साधु-संतों और धर्माचार्यों में फर्क ही क्या है? शंकराचार्य ने टकराव का रास्ता चुना है, लेकिन इस लड़ाई में नैतिक बल किसके पास ज्यादा है, यह भी तय होगा। बावजूद इसके सनातन की झंडाबरदार दो शीर्ष जातियों के बीच यह दुःसाध्य संघर्ष न सनातन के हित में है, न हिंदू हित में है और न ही देशहित में है।